राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उतरांचल, उतराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण मंगलवार 14 जुलाई 2026 वर्ष-9,अंक-162 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

पहला कॉलम

पब में लगी आग- जान बचाने टॉयलेट में छिपे वहीं पिघल गए, 27 की मौत

पब में लगी आग- जान बचाने टॉयलेट में छिपे वहीं पिघल गए, 27 की मौत

हादसे में 63 झुलसे, 22 की हालत गंभीर

बैंकॉक।

थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक पब में रविवार देर रात भीषण आग लगने से कम से कम 27 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 63 अन्य घायल हो गए। घायलों में से 22 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। यह हादसा बैंकॉक के चाटुचाक डिस्ट्रिक्ट में स्थित रॉन्ग बीयर ना लाट प्राओ बार में रात करीब 11 बजकर 57 मिनट पर हुआ। हादसे के बाद तुरंत हरकत में आए दमकल कर्मियों ने आधे घंटे में ही आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में पब के मुख्य दरवाजे से आग की लपटें निकलती दिख रही हैं और लोग जान बचाने के लिए अफरा-तफरी में भागते नजर आ रहे हैं, जबकि आसमान में काले धुएं का गुबार उठ रहा था। घटनास्थल पर पहुंचे थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चर्नविराकुल ने संवाददाताओं को बताया कि आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उन्होंने उस संगीतकार से बात की थी जो आग लगने के समय परफॉर्म कर रहा था। संगीतकार ने बताया कि आग आउट स्विच के पास लगी थी और उसके बाद घटनाक्रम तेजी से हुए, धमाके होने लगे और सभी लोग धुएं और लपटों से दूर भाग रहे थे। प्रधानमंत्री ने आगे बताया कि कई लोग इसलिए भी नहीं बच पाए, क्योंकि वे बाहर नहीं निकल पाए। इसकी वजह थी कि वे बिल्डिंग के पीछे चले गए थे और धुएं और लपटों से बचने के लिए टॉयलेट में छिपने की कोशिश कर रहे थे, और वहीं हमें सबसे ज्यादा शव मिले हैं। यह मंजर बेहद डरावना और दिल दहला देने वाला था, जहां लोग मौत से बचने के लिए आखिरी कोशिश में थे। शवों को रखने के लिए बॉडी बैग्स रखे आग पर काबू पाए जाने के बाद, बार के बाहर बड़ी संख्या में शवों को रखने के लिए बॉडी बैग्स रखे थे, जो त्रासदी की भयावहता को बयां कर रहे थे।

केंद्र में भी लागू होगी यूसीसी, यह संवैधानिक दायित्व- मुख्तार नकवी

नई दिल्ली ।

भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को केंद्र में लागू करने की बात कही है, इस उन्होंने मोदी सरकार का संवैधानिक दायित्व बताया। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद नकवी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस दशकों से यूसीसी लागू करने की बातें करती रही है, लेकिन सत्ता में आने पर न राज्यों में लागू किया और न ही केंद्र में कोई ठोस पहल की। अब जब विभिन्न राज्यों में यूसीसी लागू हो रही है, तब कांग्रेस को इसका स्वागत करना चाहिए। उन्होंने विश्वास दिलाया कि केंद्र सरकार भी उचित समय पर दिशा में आगे बढ़ेगी। राम मंदिर चढ़ावा मामले पर नकवी ने कहा कि मंदिर आंदोलन से जुड़े संवेदनशील लोग निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मंदिर प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार सभी ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। नकवी ने उन लोगों पर निशाना साधा जिनका मंदिर आंदोलन में कोई योगदान नहीं था, और अब वे राजनीतिक लाभ के लिए अनावश्यक सवाल उठा रहे हैं।

भारत में शेख हमद के निधन पर एक दिन का राष्ट्रीय शोक

-कतर को वैश्विक आर्थिक और कूटनीतिक शक्ति बनाने वाले पूर्व अमीर का 74 वर्ष की आयु में निधन

नई दिल्ली।

कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन पर भारत सरकार ने सोमवार को एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें दूरदर्शी नेता और भारत का सच्चा मित्र बताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। हालांकि, कतर की ओर से उनके निधन का कारण सार्वजनिक नहीं किया गया है। गौरतलब है कि शेख हमद बिन खलीफा अल थानी ने वर्ष 1995 से 2013 तक कतर पर शासन किया। उनके नेतृत्व में कतर ने एक छोटे खाड़ी देश से वैश्विक आर्थिक, ऊर्जा और कूटनीतिक शक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाई। प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार का प्रभावी उपयोग कर उन्होंने कतर को दुनिया के सबसे बड़े तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) निर्यातकों में शामिल कराया और देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धियों में अंतर्राष्ट्रीय समाचार नेटवर्क अल जज़ीरा की स्थापना और विस्तार शामिल है, जिसने कतर को वैश्विक मीडिया परिदृश्य में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। इसी अवधि में कतर एयरवेज का भी तेजी से विस्तार हुआ और देश ने वर्ष 2022 फीफा विश्व कप की मेजबानी का अधिकार हासिल किया। यह पहली बार था जब फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किसी मध्य-पूर्वी देश में हुआ। शेख हमद वर्ष 1995 में सत्ता में आए थे। उन्होंने अपने पिता शेख खलीफा बिन हमद अल थानी को बिना किसी हिंसा के सत्ता से हटाकर शासन संभाला था।

बोस्टन की परेड ऑफ सेल्स में तरिंगा लहराएगा आईएनएस सुदर्शिनी

बोस्टन।

भारतीय नौसेना का सेल ट्रेनिंग शिप (एसटीएस) आईएनएस सुदर्शिनी बोस्टन पहुंच गया है। यहां वह सेल बोस्टन 2026 के तहत होने वाली %परेड ऑफ सेल% में हिस्सा लेगा। इस कार्यक्रम में 20 से ज़ेयादा देशों के 60 से अधिक बड़े पारंपरिक जहाज शामिल हो रहे हैं। भारतीय नौसेना ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ÷लोकायन26, बोस्टन में तिरंगा! न्यूयॉर्क में शानदार समारोह के बाद आईएनएस सुदर्शिनी 12 जुलाई 2026 को बोस्टन पहुंचा। यहां वह सेल बोस्टन 2026 की ग्रैंड परेड ऑफ सेल्स में 20 से ज़ेयादा देशों के 60 से अधिक शिप के साथ हिस्सा लेगा।÷ उन्होंने बताया कि बोस्टन में भारत के महावाणिज्य दूत रघुराम शास्त्री ग्रैंड परेड ऑफ सेल्स और जहाज के औपचारिक स्वागत के लिए आईएनएस सुदर्शिनी पर सवार हुए। उन्होंने कहा, ÷नॉरफॉक से बोस्टन तक, लोकायन 2026 अभियान भारत की समुद्री विरासत और दोस्ती का संदेश दुनियाभर में लेकर आगे बढ़ रहा है।

÷ इससे पहले आईएनएस सुदर्शिनी ने 4 जुलाई को न्यूयॉर्क में आयोजित इंटरनेशनल नेवल रिव्यू 250 और सेल 250 समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ये कार्यक्रम अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित किए गए थे।

अब यह जहाज समुद्री सहयोग, दोस्ती और सद्भाव का संदेश लेकर बोस्टन पहुंचा है, जहां वह सेल बोस्टे टन 2026 में हिस्सा लेगा। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, आईएनएस सुदर्शिनी ने आठ जुलाई को न्यूयॉर्क का अपना दौरा सफलतापूर्वक पूरा किया। यह उसके चल रहे लोकायन 2026 समुद्री अभियान का एक और अहम पड़ाव रहा। मंत्रालय ने कहा

कि इस यात्रा के दौरान भारत की समृद्ध समुद्री विरासत दुनिया के सामने पेश की गई और भारत-अमेरिका के बीच रणनीतिक और सांस्कृतिक रिश्तों को भी और मजबूती मिली।

दिल्ली-यमुनोत्री हाईवे पर बांध का हिस्सा ढहा,देहरादून में पुल बहा

दिल्ली-यमुनोत्री हाईवे पर बांध का हिस्सा ढहा, देहरादून में पुल बहा

- मॉनसून का कहर- 120 सड़कें बंद, अलर्ट जारी

देहरादून।

उत्तराखंड में मॉनसून ने कहर बरपाया है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राज्यभर में कुल 120 सड़कें बंद हो गई हैं, जिसके कारण आम लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे गंभीर घटनाओं में लखवाड़ बहुउद्देश्यीय बांध परियोजना का निर्माणाधीन हिस्सा भरभराकर दिल्ली-यमुनोत्री हाईवे पर गिर गया। इस घटना में निर्माण कंपनी के कई वाहन और उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए, हालांकि राहत की बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, क्योंकि श्रमिक-कर्मचारी हादसे के वक्त दूसरे हिस्से में काम कर रहे थे। मलबे के कारण हाईवे पर काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल रहा, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद रविवार सुबह तक मलबा हटाकर यातायात सामान्य कर दिया गया। यूजेवीएनएल के जनसंपर्क अधिकारी ने इस घटना को बरसात के दौरान निर्माण कार्यों में आने वाली सामान्य प्रक्रिया बताया है।दूसरी ओर, देहरादून के प्रेमनगर में नंदा की चौकी के पास टौंस नदी पर बना अस्थायी पुल शनिवार रात तेज बहाव में बह गया। इससे रविवार सुबह लगभग 11 बजे तक आवाजाही ठप रही और लोगों को दस किलोमीटर घूमकर जाना पड़ा। लोक निर्माण विभाग को आनन-फानन में नए पुल पर यातायात खोलना पड़ा, जिससे करीब 11 घंटे बाद लोगों को राहत मिल सकी। इन घटनाओं ने बारिश के दौरान निर्माण कार्यों

और अस्थायी इंतजामों की मजबूती पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मौसम विभाग ने सोमवार के लिए भी देहरादून सहित रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़ और नैनीताल जैसे छह जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर बारिश और आकाशीय बिजली चमकने के साथ तीव्र से अति तीव्र वर्षा का दौर चलने की भी आशंका है। लोगों को संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। राज्यभर में बंद पड़ी 120 सड़कों में पौड़ी में सर्वाधिक 20, चमोली में 17, पिथौरागढ़ में 14 और उत्तरकाशी में लगभग 15 सड़कें शामिल हैं।

लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के अनुसार, भूस्खलन की बड़ी मात्रा के कारण कुछ सड़कों को खोलने में समय लग रहा है, लेकिन सभी डिविजनों को सड़क संपर्क बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं।

देश में मानसून ने भरी हुंकार बिहार-बंगाल में रेड अलर्ट

देश में मानसून ने भरी हुंकार- बिहार-बंगाल में रेड अलर्ट

- उत्तराखंड में आफत और दिल्ली में राहत

नई दिल्ली ।

देशभर में मानसून अब अपनी पूरी रफ्तार पकड़ चुका है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, आज बारिश का सबसे ज्यादा असर उत्तर, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में देखने को मिल सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, इस समय मानसून ट्रफ श्रीगंगानगर से होते हुए हिसार, मेरठ, शाहजानकारी, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर और दक्षिण असम तक फैली हुई है। इसके साथ ही एक पश्चिमी विक्षोभ और बिहार-बांग्लादेश के ऊपर बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन (चक्रवाती परिसंचरण) मानसून को अतिरिक्त ताकत दे रहे हैं। यही वजह है कि अगले 24 घंटे कई राज्यों के लिए भारी बारिश वाले साबित हो सकते हैं।बिहार और पश्चिम बंगाल में रेड ज़ोन जैसी स्थितिबिहार के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। लगातार बरसात के कारण निचले इलाकों में जलभराव, छोटी नदियों के उफान और स्थानीय बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। यहाँ गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की भी आशंका है। पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। झारखंड और ओडिशा में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा। हालांकि, ओडिशा के तटीय इलाकों में लोगों को गर्म और उमस भरे मौसम का भी सामना करना पड़ेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून जमकर बरसेगा। गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बलिया, वाराणसी और आसपास के जिलों में भारी बारिश के साथ गरज-चमक और बिजली गिरने की आशंका है। वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा।

असम-मेघालय सहित सभी सातों राज्यों में अलर्ट

असम और मेघालय में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है, जिसके चलते अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा- इन राज्यों में भी तेज बारिश और आकाशीय बिजली की चेतावनी जारी की गई है। पूर्वोत्तर में मानसून अपनी पूरी ताकत से बरस रहा है।

पहाड़ी इलाकों में आफत, जम्मू-कश्मीर में भी बारिश

उत्तराखंड- उत्तर भारत में उत्तराखंड सबसे संवेदनशील राज्य बना हुआ है। लगातार भारी बारिश के अलर्ट के बीच पर्वतीय इलाकों में भूस्खलन (लैंडस्लाइड), चट्टान गिरने और अचानक बाढ़ (फ्लैश फ्लड) का खतरा है। चारधाम यात्रा मार्गों पर जाने वाले श्रद्धालुओं को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। जम्मू-कश्मीर में भी कुछ स्थानों पर गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है।

दिल्ली-एनसीआर में राहत की फुहारें

दिल्ली-एनसीआर में मौसम राहत भरा रहेगा। दिनभर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि लगातार बारिश की संभावना कम है, लेकिन रुक-रुक कर होने वाली फुहारें लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत देंगी।

आईएमडी के मुताबिक, अगले सात दिनों तक दिल्ली के अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है और मौसम सुहावना बना रहेगा। हालांकि, कुछ इलाकों में अचानक तेज बारिश से ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है। मध्य प्रदेश से गोवा तक बरसेंगे बादल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ- इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय पर कसेगा शिकंजा

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय पर कसेगा शिकंजा

अयोध्या।

अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावे की चोरी और जमीन सौदों से जुड़े गंभीर आरोपों के बाद, विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने हिंदू धर्मसेना प्रमुख संतोष दुबे से लंबी पूछताछ कर उनका बयान दर्ज किया है। दुबे, जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी हैं, लगातार राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और अन्य पदाधिकारियों पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगाते रहे हैं। एसआईटी ने इन आरोपों के संबंध में संतोष दुबे से दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध कराने को कहा है, जिन्हें वे पेश करेंगे। यह पूछताछ पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर कार्यालय में वर्चुअल माध्यम से करीब आधे घंटे तक चली, जिसमें एसआईटी सदस्य किरण एस ने आरोपों के बारे में सिलसिलेवार सवाल पूछे। इनके बयानों के बाद माना जा रहा है कि चंपत राय पर शिकंजा कसा जा सकता है।

संतोष दुबे ने एसआईटी को बताया कि राम मंदिर से चढ़ावे की चोरी लंबे समय से हो रही है, और इस मामले में छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाया गया है, जबकि असल जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने 2002 में 1250 राम शिलाओं की चोरी का भी जिक्र किया और कहा कि उनके पास चढ़ावा चोरी से जुड़ी रकम और अन्य अनियमितताओं का विस्तृत ब्योरा है। इसके अलावा, दुबे ने ट्रस्ट पर कम कीमत की जमीन को दोगुने से ज्यादा कीमत में खरीदने का भी आरोप लगाया है।

सभा में नरोत्तम मिश्रा की आंखें छलक आई उनका गला भर आया

सभा में नरोत्तम मिश्रा की आंखें छलक आई उनका गला भर आया

दतिया

पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा चुनाव में टिकट न मिलने का गम सह नहीं पा रहे हैं 7 यह आज भी देखने को मिला जब दतिया में बीजेपी की सभा में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की आंखें छलक गईं। उनका गला भर आया, आवाज भर्रा उठी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा- कांग्रेस कहती है कि भाजपा में फूट है। देख लीजिए, हम सब यहां साथ खड़े हैं। मैं इस उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को जिताने दतिया के एक-एक घर के सामने शीश नवाऊंगा।नरोत्तम ने कहा- कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह यानी राजा साहब एक्सपायरी डेट की होम्योपैथी की गोली हैं। वो बहुत मीठी होती है, लेकिन असर कुछ नहीं होता। वहीं, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा- नरोत्तम, हम छोटे भाई आशुतोष तिवारी को आपके सुपुर्द कर रहे हैं।आज पूरे उत्साह के साथ बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने दोपहर करीब ढाई बजे नामांकन भरा। मुख्यमंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा सहित दूसरे पार्टी नेता उनके साथ रहे।

पीएम मोदी की यात्रा पर बीजेपी, वे सफल होकर लौटे, राहुल गांधी देश खिलाफ साजिश...

नई दिल्ली।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीन देशों की विदेश यात्राओं को देश के लिए आर्थिक और रणनीतिक रूप से सफल बताया है। इसके साथ ही, पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भारत के खिलाफ कथित बयान देने को लेकर तीखा हमला किया है। बीजेपी पार्टी मुख्यालय में प्रेसवार्ता को संबोधित कर भाजपा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया यात्राओं के परिणामों का विस्तार से उल्लेख किया।

बीजेपी सांसद पात्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की इन यात्राओं से आर्थिक और निवेश के क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं।

उन्होंने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए यूरेनियम आपूर्ति समझौते को रेखांकित किया। भाजपा ने समझौते की तुलना पिछली यूपीए सरकार की नाकामी से की, यह याद दिलाकर कि 2010 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को यूरेनियम की आपूर्ति करने से इंकार किया था। बीजेपी नेता पात्रा ने दावा किया कि अब, पीएम मोदी के नेतृत्व में, ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम उपलब्ध कराएगा।

प्रधानमंत्री मोदी के तीन देशों के दौरे के नतीजों का जिक्र कर पात्रा ने रक्षा और समुद्री सहयोग पर अहम समझौतों के साथ-साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी (सीएसपी) पर हस्ताक्षर होने की बात कही। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स और आवश्यक खनिजों के क्षेत्र में 35 देशों के साथ समझौते किए हैं, जो देश की रणनीतिक आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण हैं।

इन उपलब्धियों को गिनाकर पात्रा ने राहुल गांधी पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी पर चीन के एजेंट की तरह काम करने और भारत के खिलाफ बयान देने का

आरोप लगाया। पात्रा ने आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और वहां भारत के खिलाफ बयान दिए।

उन्होंने कांग्रेस नेता का मज़ाक उडाकर कहा कि जहां प्रधानमंत्री मोदी देश के लिए जीत हासिल करके लौटे हैं, वहीं राहुल गांधी, जो अभी विदेश में हैं, क्या बंद कमरों में भारत के खिलाफ साजिश रचाने का काम कर रहे है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

गोल्ड मेडल बनाम कड़ाही का हलवा: कब तक किचन से नपेगी महिलाओं की उड़ान?

लेखिका - निमिषा सिंह

बधाई हो भारत! बधाई हो कानपुर यूनिवर्सिटी की उन बयासी प्रतिशत मेडल लाने वाली बेटियों को, जिन्होंने अपनी मेधा, अपने संघर्ष और अपनी रातों की नींद एक करके अकादमिक दुनिया के सर्वोच्च शिखर को छुआ है। यह आंकड़ा केवल एक सामान्य संख्या या कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि यह उस बदलते भारत की एक गूंजती हुई हुंकार है जो सदियों की सामाजिक बेड़ियों और घरेलू चारदीवारी को मरोड़कर बाहर निकल रहा है। लेकिन ठहरिए! ज़रा अपनी इस ऐतिहासिक कामयाबी का जश्न मनाना बंद कीजिए। अपनी डिग्रियों को आलमारी के किसी अंधेरे कोने में बंद करिए, मेडल को गले से उतारिए और चुपचाप हाथ में पेन-कॉपी या लैपटॉप की जगह कलछी, कड़ाही और बेलन थाम लीजिए। क्योंकि देश के एक सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठीं आदर्श महिला ने यह पूरी तरह साफ़ कर दिया है कि आपके इन तमाम गोल्ड मेडलों की औकात ससुराल के किचन में बनने वाले उस एक कटोरी सूजी के हलवे से ज्यादा कुछ नहीं है, जिसे खाकर आपकी सास को आत्मिक संतुष्टि मिल सके और वे समाज के सामने आपको एक संस्कारी बहू होने का प्रामाणिक सर्टिफिकेट दे सकें।

यह बेहद विडंबनापूर्ण, निराशाजनक और लोकतांत्रिक मूल्यों को पूरी तरह से शर्मसार करने वाला दृश्य है कि जब देश की बेटियां तमाम सामाजिक, मानसिक और आर्थिक बाधाओं को पार करते हुए अकादमिक क्षेत्र में बयासी प्रतिशत पदकों पर अपना एकछत्र कब्ज़ा जमा रही हैं, तब उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को उनके इस सुनहरे, उज्ज्वल और गौरवमयी भविष्य में सिर्फ एक कच्चा-पक्का हलवा और सास की गालियां ही दिखाई दे रही हैं। महामहिम का दीक्षांत समारोह के उस पावन मंच से दिया गया यह बयान केवल एक सामान्य प्रशासनिक या औपचारिक भाषण नहीं है, बल्कि यह उस गहरी और सड़ी-गली पितृसत्तात्मक सोच का जीता-जागता और भयावह दस्तावेज़ है, जो महिलाओं की हर सफलता, उनकी हर अद्वितीय योग्यता और उनके पूरे अस्तित्व को हमेशा किचन की चौखट और घरेलू गुलामी के तराजू पर ही तौलती आई है।

एक राज्य की मुखिया और विश्वविद्यालय की कुलाधिपति से यह उम्मीद थी कि वे उन मेधावी, ऊर्जावान और आकांक्षी लड़कियों को यह सिखाएंगी कि आने वाले समय में उन्हें कॉर्पोरेट जगत के शीशे की अदृश्य छतों को कैसे ध्वस्त करना है। उनसे उम्मीद थी कि वे उन्हें मुक्केबाज़ी, कराटे, आत्मरक्षा, खेल और प्रशासनिक दुनिया में पुरुषों के ऐतिहासिक एकाधिकार को चुनौती देने के लिए भीतर से प्रेरित करेंगी। वे मंच से दहाड़ कर कहेंगी कि लड़कियों, यह पूरी कायनात तुम्हारी है, अपने पंख फैलाओ और पूरी ताकत से आसमान में उड़ जाओ! लेकिन अफ़सोस, महामहिम ने उस ऐतिहासिक दीक्षांत समारोह के मंच को किसी तीसरे दर्जे के सास-बहू वाले टीवी धारावाहिक का सेट समझ लिया। वे देश की भावी वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, प्रोफेसरों और प्रशासनिक अधिकारियों को यह दकियानूसी ज्ञान बांटने लगीं कि चाहे तुम कलेक्टर बनो, प्रोफेसर बनो या देश की आईएएस ऑफिसर बनो, पहले एक एक्सपर्ट मां और बावर्ची बनो, क्योंकि ससुराल में तुम्हारा पहला और अंतिम इम्तिहान तो मोबाइल देखकर बनाए गए हलवे का ही होगा।

हम जैसी महिलाएं जो रोज़ धरातल पर पत्रकारिता कर रही हैं, जो सामाजिक एक्टिविज़्म के ज़रिए हाशिए की, ग्रामीण और शोषित महिलाओं के बीच जाकर दिन-रात यह अलख जगा रही हैं कि किचन के बाहर भी एक बेहद आज़ाद, गरिमापूर्ण और मुकम्मल दुनिया सांस ले रही है, आपके इस एक गैर-जिम्मेदाराना बयान ने हमारी सालों की मेहनत और संघर्ष पर पानी फेरने का आत्मघाती काम किया है। मैडम, आपने लड़कियों को तो बड़े प्यार और अधिकार से समझा दिया कि वे रो-धोकर, अपमानित होकर और गालियां खाकर भी हलवा बनाना सीखें और चुपचाप ससुराल के हर अत्याचार को नियति मानकर सहें। लेकिन आपने उस पूरे हॉल में बैठे लड़कों, उनके अहंकारी पिताओं और भावी पतियों को यह क्यों नहीं सिखाया कि अगर तुम्हें हलवा खाना इतना ही पसंद है, तो रसोई में जाकर खुद अपने हाथों से उसे बनाना क्यों नहीं सीख लेते? पतियों को एक संवेदनशील इंसान बनने, एक सच्चा सहयात्री बनने और घरेलू ज़िम्मेदारियों को आधा-आधा बांटने की सीख क्यों नहीं दी गई? क्या पुरुषों को इस समाज में सिर्फ बैठकर हुक्म चलाने, दूसरों की थाली में नुक्स निकालने और गालियां देने के लिए विशेषाधिकार प्राप्त है?

मैं अपने पत्रकारिता और सामाजिक जीवन के कड़वे अनुभवों से शुरू से एक बात पुरज़ोर तरीके से कहती आई हूँ, और आज की यह घटना मेरी उस वैचारिक समझ पर एक और पक्की और मुकम्मल मुहर लगाती है कि आज के आधुनिक दौर में पितृसत्तात्मक विचारों की असली संवाहक और रक्षक पुरुष नहीं, बल्कि खुद समाज के शीर्ष पर बैठीं कुछ रूढ़िवादी महिलाएं बन चुकी हैं। यह देखना और महसूस करना इस दौर की सबसे कड़वी और दुखद हकीकत है। जिस पुरुषवादी सामाजिक व्यवस्था ने सदियों से महिलाओं का दमन किया, उन्हें पढ़ने के अधिकारों से वंचित रखा, उन्हें चारदीवारी में कैद रखा, आज उसी दमनकारी व्यवस्था की पहरेदारी, वकालत और चौकीदारी करने के लिए समाज की शीर्ष पदों पर बैठी महिलाएं खुद आगे आ रही हैं। आनंदीबेन पटेल का यह बयान कोई समाज में इकलौती या नई घटना नहीं है।

अगर हम सत्ता के ऊंचे गलियारों में झांकें, तो हमें ऐसे आत्मघाती और महिला-विरोधी बयानों की एक लंबी और शर्मनाक फेहरिस्त दिखाई देगी। जब देश की पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी संसद के भीतर खड़े होकर महिलाओं के सबसे बुनियादी जैविक और स्वास्थ्य अधिकारों को पूरी तरह से खारिज करते हुए पेड पीरियड लीव यानी मासिक धर्म की छुट्टी का पुरज़ोर विरोध करती हैं, तो वे भी इसी पितृसत्ता की एक मजबूत पहरेदार के रूप में खड़ी नज़र आती हैं। जब पश्चिम बंगाल जैसी संवेदनशील राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किसी वीभत्स और जघन्य गैंगरेप को सरेआम एक सजाई हुई घटना या सिर्फ एक प्रेम प्रसंग का बिगड़ना कहकर पीड़ितों की प्रामाणिकता और उनके चरित्र पर ही सवाल उठा देती हैं, तो न्याय की अंतिम उम्मीद भी वहीं दम तोड़ देती है।

जब महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए बने राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रेखा शर्मा अपराधियों और बलात्कारियों पर नकेल कसने के बजाय आधुनिक लड़कियों को ही देर रात बाहर न निकलने की ढालू और कायरतापूर्ण नसीहतें देने लगती हैं, तब रक्षक ही भक्षक सा महसूस होने लगता है। और हम भारतीय समाज के मानस से उस घटना को कैसे भूल सकते हैं जब दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने एक महिला पत्रकार की मर्डर मिस्ट्री पर गैर-जिम्मेदाराना तरीके से यह कहकर पल्ला झाड़ लिया था कि महिलाओं को इतनी देर रात अकेले बाहर निकलकर ज्यादा साहसी नहीं होना चाहिए।

ये तमाम राष्ट्रीय उदाहरण इस बात की चीख-चीख कर गवाही देते हैं कि जब महिलाएं ही अपने भीतर की ऐतिहासिक कंडीशनिंग से खुद को मुक्त नहीं कर पातीं और व्यवस्था के शीर्ष पर बैठकर दूसरी संघर्षशील महिलाओं के पैरों में समाज की बनाई पुरानी बेड़ियां डालने लगती हैं, तो पितृसत्ता को किसी पुरुष की लाठी या किसी सामाजिक सहारे की कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाती। यही वह आत्मघाती सोच है, जिसके कारण समाज की अनगिनत बेटियां, चाहे कितनी भी बड़ी-बड़ी डिग्रियां ले लें, चाहे वे जज, डॉक्टर या कलेक्टर ही क्यों न बन जाएं, अंततः दहेज, घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना की भट्टी में चुपचाप झोंक दी जाती हैं। क्योंकि यह तथाकथित सभ्य समाज उन्हें पहले एक स्वतंत्र, तार्किक और संप्रभु इंसान के रूप में स्वीकार ही नहीं कर पाता; वह उन्हें हमेशा पुरुषों की एक सेवादार और अनुगामी के रूप में ही देखना चाहता है।

महामहिम और उनके जैसी संकीर्ण सोच रखने वाले इस पूरे समाज को हम आज साफ़-साफ़ और कड़े शब्दों में यह चेता देना चाहती हैं कि महिलाएं कोई रोबोट, मशीन या कोई खिलौना नहीं हैं जिनका इस धरती पर अल्टीमेट गोल सिर्फ बच्चे पैदा करना, पुरुषों का वंश बढ़ाना और उनके लिए गोल रोटियां सेंकना है। हम एक स्वतंत्र, तार्किक, बौद्धिक और पूर्णतः संप्रभु इंसान हैं। हमारी शिक्षा, हमारी डिग्रियां और हमारी नौकरियां हमारी खुद की आर्थिक आज़ादी, हमारे स्वाभिमान और इस पूरे देश के विकास के लिए हैं, किसी के रूढ़िवादी घर को परेशानी-मुक्त रखने का गुलामी-पत्र नहीं।

कानपुर यूनिवर्सिटी और देश की हर एक यूनिवर्सिटी की उन तमाम जुझारू और मेधावी बेटियों को हमारा सीधा और स्पष्ट संदेश है कि अपने इन गोल्ड मेडल्स को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। पढ़ना, लड़ना, हर गलत परंपरा पर तीखे सवाल करना और पुरुषों के समकक्ष खड़े होकर इस सड़ी-गली व्यवस्था को चुनौती देना ही तुम्हारा पहला और अंतिम दायित्व है। रही बात हलवे की, तो जिसे भी हलवा खाना होगा, वह अपनी भूख और पसंद के अनुसार खुद रसोई में जाएगा, गैस जलाएगा और बना लेगा। अब देश की आधी आबादी आपकी इस दकियानूसी, महिला-विरोधी और हलवा-मार्का सोच के पिंजरे में दोबारा बंद होने वाली नहीं है। हम बेखौफ उड़ना सीख चुकी हैं, और अब आसमान से नीचे हमें कुछ भी मंजूर नहीं।

(यह ले खिका के व्य क्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अ निवार्य नहीं है)

संपादकीय

ज़हरीली विरासत

शासन-प्रशासन के तमाम दावों के बावजूद आज भी पंजाब की नदियों को जहरीला बनाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जिसकी पुष्टि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्वीकृति है कि आज भी आठ सौ से अधिक प्रदूषण के स्रोत राज्य की नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं। निश्चय ही यह तथ्य उन विभागों व संस्थाओं के कामकाज पर सवालिया निशान है जो पर्यावरण संरक्षण के प्रबंधन से जुड़े हैं। साथ ही लंबे समय से अदालत के हस्तक्षेप व विभिन्न सर्वेक्षणों में सामने आए तथ्यों की पुष्टि होती है कि राज्य में जागरूकता की कमी नहीं है, बल्कि समय रहते प्रभावी कार्रवाई न होने से उपजा संकट है। वर्षों से सरकारें एक्शन प्लान बनाने के दावे करती रही हैं। कभी ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की बात होती है तो कभी कमेटियां बनाने के दावे होते हैं। आखिर क्यों आज भी बिना साफ किया हुआ सीवेज और औद्योगिक कचरा सतलुज,ब्यास और इनकी सहायक नदियों में बदस्तूर बहाया जा रहा है। जाहिर है, मौजूदा संसाधनों का या तो पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है या उनका रखरखाव ठीक नहीं है। फलतः जन-स्वास्थ्य से जुड़ा एक बड़ा संकट पैदा होता है। जो धीरे-धीरे आपदा का रूप ले लेता है। आज फैक्ट्रियों से निकलने वाले रसायनों के जरिये भारी धातुएं और जहरीले तत्व भूजल को प्रदूषित करने के बाद, हमारी खाद्य श्रृंखला में शामिल हो रहे हैं। जो राज्य के बहुचर्चित ' कैंसर बेल्ट' के रूप में हमारे सामने मौजूद है। निस्संदेह, पंजाब में यदि हरित क्रांति का परचम लहराया तो उसके मूल में पंजाब की नदियों की बड़ी भूमिका रही है। लेकिन आज वे तंत्र की काहिली, अनियोजित शहरीकरण, नियम-कानूनों का क्रियान्वयन न होने और दोषियों को सजा न मिलने का दंड चुका रही हैं। एनजीटी गाहे-बगाहे नगर निकायों की शिथिलता दर्शाकर सच्चाई से आम लोगों को अवगत कराता रहा है। निस्संदेह, पर्यावरण संरक्षण के प्रयास तब तक सफल नहीं हो सकते हैं जब तक कि इसकी जिम्मेदारी तय न की जाए और सख्त जुर्माना लगाना पर्यावरण संरक्षण नीति का हिस्सा नहीं बनता है। राज्य ने साबित किया है कि मरणासन्न नदियों को फिर से जीवित किया जा सकता है। काली बेईं को पुनर्जीवित करने में जागरूक लोगों की बड़ी भूमिका रही है। जो दर्शाता है कि पक्के इरादे के साथ किए गये प्रयास से बेहद बुरे हालात में पहुंच चुके जल स्रोत को भी जीवंत बनाया जा सकता है। लेकिन इक्का-दुक्का सफलताएं ही व्यापक रणनीति की जगह नहीं ले सकतीं। जरूरी है कि नियम-कानूनों का कड़ाई से पालन किया जाए, सार्वजनिक रिपोर्टिंग को पारदर्शी बनाएं तथा सीवेज एवं कचरा-शोधन प्रणालियों में निरंतर निवेश बढ़ाया जाए। सर्वविदित है कि पंजाब का नाम यहां की नदियों से पड़ा है। ऐसे में इन नदियों को खुले नाले बनते रहने देने से न केवल हमारा पारिस्थितिकीय तंत्र व लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है, बल्कि राज्य की खुशहाली व पहचान के लिये भी एक खतरा है। अब मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाने का वक्त है।

सुप्रीम कोर्ट की गरिमा और न्याय की संवेदना

(लेखक-कांतिलाल मांडोत)

देश की सबसे बड़ी अदालत में मर्यादा भी सर्वापरि और पीड़ित की पीड़ा को समझना भी उतना ही आवश्यक

देश की सर्वोच्च अदालत केवल एक न्यायिक संस्था नहीं है, बल्कि संविधान की आत्मा और लोकतंत्र की अंतिम आशा का केंद्र है। जब देश का कोई नागरिक हर स्तर पर न्याय की तलाश में असफल होकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, तो उसके मन में यही विश्वास होता है कि यहां उसकी बात निष्पक्षता और संवेदनशीलता के साथ सुनी जाएगी। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट की गरिमा, मर्यादा और प्रतिष्ठा पूरे न्यायिक तंत्र की आधारशिला मानी जाती है। अदालत की गरिमा बनाए रखना जितना न्यायाधीशों और न्यायिक कर्मचारियों का दायित्व है, उतना ही वहां उपस्थित प्रत्येक अधिवक्ता, याचिकाकर्ता और नागरिक का भी कर्तव्य है।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक याचिकाकर्ता वकील द्वारा न्यायाधीशों के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करना, कागजात उछालना और मुख्य न्यायाधीश के लिए अपशब्द कहना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। किसी भी परिस्थिति में न्यायालय के भीतर इस प्रकार का व्यवहार स्वीकार्य नहीं कहा जा सकता। अदालत तर्क और कानून की भाषा समझती है, आक्रोश और अपमान की नहीं। यदि न्याय की लड़ाई लड़ने वाला स्वयं कानून और शिष्टाचार की सीमाएं लांघने लगे, तो न्याय व्यवस्था पर लोगों का विश्वास कमजोर होने का खतरा पैदा हो सकता है।

वकील केवल अपने मुवक्किल का प्रतिनिधि नहीं होता, बल्कि वह न्यायालय का भी अधिकारी माना जाता है। उसकी वाणी, उसका आचरण और उसका व्यवहार न्यायपालिका की गरिमा से जुड़ा होता है। इसलिए अधिवक्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे कठिन से कठिन परिस्थिति में भी संयम बनाए रखें। असहमति व्यक्त करने का अधिकार सभी को है, लेकिन असहमति और अभद्रता के बीच एक स्पष्ट रेखा होती है। उस रेखा का सम्मान करना ही लोकतांत्रिक संस्कृति और न्यायिक परंपरा की पहचान है।

इस पूरे घटनाक्रम का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अदालत ने वकील की याचिका खारिज कर दी, लेकिन उसके खिलाफ अवमानना की कठोर कार्रवाई नहीं की। न्यायाधीशों ने यह भी कहा कि वह व्यक्ति संभवतः अत्यधिक तनाव और मानसिक दबाव में है तथा उसकी हताशा स्पष्ट दिखाई दे रही है। यह दृष्टिकोण न्यायपालिका की मानवीय संवेदना को भी सामने लाता है। कानून केवल दंड देने का माध्यम नहीं है, बल्कि परिस्थितियों को समझने और न्याय के व्यापक उद्देश्य को ध्यान में रखने की व्यवस्था भी है।

वास्तविकता यह है कि न्याय की तलाश में अदालत तक पहुंचने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी पीड़ा, संघर्ष या अन्याय का बोझ लेकर आता है। वर्षों तक मुकदमे लड़ने, आर्थिक बोझ उठाने और बार-बार अदालतों के चक्कर लगाने के बाद जब अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता, तब कई लोग मानसिक रूप से टूट जाते हैं। यह टूटन कभी-कभी हताशा और असंतुलित व्यवहार के रूप में सामने आती है। इसका अर्थ यह नहीं कि ऐसे व्यवहार को उचित ठहराया जाए, बल्कि यह समझना आवश्यक है कि उसके पीछे पीड़ा और निराशा का एक लंबा इतिहास भी हो सकता है।

न्यायपालिका की सबसे बड़ी ताकत उसकी निष्पक्षता के साथ-साथ उसकी संवेदनशीलता भी है। यदि कोई व्यक्ति अदालत में अत्यधिक तनावग्रस्त दिखाई देता है, तो उसके साथ कानून के अनुसार व्यवहार करते हुए उसकी मानसिक स्थिति को भी समझना चाहिए। न्याय केवल आदेश सुनाने से पूरा नहीं होता, बल्कि यह विश्वास भी पैदा करता है कि अदालत ने व्यक्ति की बात पूरी गंभीरता से सुनी और समझी। यही विश्वास लोकतंत्र की सबसे बड़ी पूंजी है। यह भी सच है कि न्याय में विलंब, लंबी कानूनी प्रक्रिया और बढ़ते मुकदमों का बोझ कई लोगों में निराशा पैदा करता है। ऐसे में न्याय व्यवस्था को अधिक सुलभ, सरल और समयबद्ध बनाने की दिशा में लगातार प्रयास आवश्यक हैं। जब लोगों को समय पर न्याय मिलेगा, तो निराशा और असंतोष की स्थितियां भी कम होंगी। न्याय व्यवस्था का उद्देश्य केवल विवादों का निपटारा नहीं, बल्कि समाज में विश्वास और संतुलन बनाए रखना भी है। इस घटना ने एक और संदेश दिया है कि न्यायालय की गरिमा बनाए रखने में सभी की समान जिम्मेदारी है। यदि अदालत में अनुशासन समाप्त हो जाए, तो न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होगी और इसका नुकसान अंततः आम नागरिक को ही होगा। इसलिए चाहे वह वरिष्ठ अधिवक्ता हों, नए वकील हों या स्वयं पक्षकार, सभी को यह समझना होगा कि अदालत में शब्दों का चयन, व्यवहार की मर्यादा और कानून के प्रति सम्मान सर्वोपरि है।

दूसरी ओर न्यायपालिका की उदारता भी सराहनीय है। यदि अदालत चाहती तो अवमानना की कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन उसने संयम दिखाया और कठोर दंड देने के बजाय मामले को वहीं समाप्त करना उचित समझा। यह निर्णय बताता है कि न्याय केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि विवेक, धैर्य और करुणा का संतुलित स्वरूप है। हालांकि इस उदारता का अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति अदालत की गरिमा को ठेस पहुंचाने का साहस करे। कानून का सम्मान हर परिस्थिति में अनिवार्य है। लोकतंत्र में न्यायपालिका अंतिम आशा होती है। जब प्रशासन, व्यवस्था और अन्य संस्थाओं से निराश व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, तो उसके मन में उम्मीद की आखिरी किरण बची होती है। इसलिए अदालतों को भी यह ध्यान रखना होगा कि उनके सामने खड़ा हर व्यक्ति केवल एक केस नंबर नहीं, बल्कि अपने जीवन की किसी गहरी समस्या से जूझता हुआ इंसान है। उसकी बात सुनते समय कानून के साथ मानवीय संवेदना भी बनी रहनी चाहिए। इस घटना से देश को दो महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। पहली, अदालत की गरिमा किसी भी कीमत पर भंग नहीं होनी चाहिए। न्यायालय में अपशब्द, आक्रोश और अभद्र व्यवहार लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध हैं। दूसरी, न्याय व्यवस्था को लोगों की पीड़ा, मानसिक तनाव और संघर्ष को भी समझना चाहिए, क्योंकि न्याय केवल निर्णय देने का नाम नहीं, बल्कि समाज में विश्वास बनाए रखने की प्रक्रिया है।

सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत है और उसकी प्रतिष्ठा पूरे राष्ट्र की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। वहीं, अदालत की चौखट पर आने वाला हर व्यक्ति न्याय की उम्मीद लेकर आता है। इसलिए आवश्यक है कि एक ओर अधिवक्ता और पक्षकार अपनी मर्यादा और जिम्मेदारी को समझें, तो दूसरी ओर न्याय व्यवस्था भी हर पीड़ित की व्यथा को महसूस करते हुए कानून और संवेदना के बीच संतुलन बनाए रखे। यही संतुलन भारतीय न्यायपालिका की सबसे बड़ी शक्ति है और यही लोकतंत्र की स्थायी पहचान भी।

दूसरों के दुख से अपना दुख ज्यादा बेहतर

एक कहावत है राजा दुखी, प्रजा दुखी सुखिया का दुख दुना। कहने का अर्थ यह है कि संसार में जिसे देखो वह अपने को दुखी ही कहेगा। राजा का अपना दुख है, प्रजा का अपना और जिसे आप सुखी माने बैठें हैं उससे पूछ कर देंखेंगे तो वह भी अपने दुखों की पोटरी खोलकर अपनी व्यथा गाने लगेगा। लेकिन अगर आपके पास यह विकल्प हो कि आप अपना दुख किसी और को देकर दूसरे का दुख खुद स्वीकार कर लें तब आप कहेंगे कि अपना ही दुख भला है। इस संदर्भ में एक कथा है कि किसी गांव में एक फकीर आये। उनकी विशेषता यह थी कि वे किसी की भी समस्या दूर कर देते थे। उनकी इस विशेषता के बारे जिसे भी पता चला, वह उनके पास दौड़ा आया। अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई और लोग जल्दी से जल्दी अपनी समस्या फकीर को बताने की जुगत भिड़ाने लगे।

नतीजा यह हुआ कि हर कोई बोलने लगा। कोलाहल मच गया। फकीर ने सभी को चुप होने के लिए कहा। सभी लोग चुप हो गये तब फकीर ने कहा, मैं सबकी समस्या दूर कर दूंगा। आप सब लोग एक-एक कागज पर अपनी समस्या लिखकर लाएं और मुझे दे दें। कुछ ही देर में कागजों का ढेर लग गया। फकीर ने कागजों को एक टोकरी में रखा और उसे सबके बीच में रख दिया। एक आदमी की तरफ इशारा करके फकीर मे कहा, यहां से शुरू करके सब बारी-बारी से आएंगे और एक-एक कागज उठा लें।

ध्यान रहे किसी को अपना कागज नहीं उठाना है। लोग एक-एक कर आए कागज उठा-उठा कर अपनी-अपनी जगह बैठ गए। फकीर ने कहा, अब इस कागज में लिखी किसी दूसरे की समस्या पढ़ो। अगर चाहो तो मैं तुम्हारी समस्या दूर कर दूंगा पर उसके बदले कागज पर लिखी समस्या तुम्हारी हो जाएगी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी समस्या बड़ी है तो उसे दूर करवाकर कागज पर लिखी दूसरे की छोटी-सी समस्या अपना लो। चाहो तो आपस में कागज बदल लो। जब तय कर लो कि अपनी समस्या के बदले कौन सी समस्या लोगे तो मेरे पास आ जाना। लोगों ने जब अपने पास कागज पर लिखी समस्या पढी तो वे घबरा गए। लोग एक दूसरे से कागज बदल-बदल कर पढ़ रहे थे। हर बार उन्हें लगता कि उनकी समस्या तो जैसी है वैसी है, पर इस नई समस्या का सामना नहीं कर पाएंगे। कुछ देर में हर किसी को समझ आ गया कि उनकी समस्या जैसी भी है उनके अपने जीवन का हिस्सा है और वे उसी का सामना कर सकते हैं। एक-एक कर के लोग चुपचाप वहाँ से चले गये।

विचार मंथन

ई-20 को लेकर जन आंदोलन की तैयारी, एवरेज और गाड़ियां बर्बाद

(लेखक- सनत जैन)

सरकार ने भारत के सभी पेट्रोल पंपों पर ई-20 पेट्रोल को अनिवार्य कर दिया है। पिछले 1 महीने से इस पेट्रोल के कारण देशभर के सभी राज्यों से गाड़ी का एवरेज कम होने और गाड़ियों में तरह-तरह से खराबी की शिकायतें बड़े पैमाने पर आना शुरू हो गई हैं। जिसके कारण लोगों में गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। दो पहिया और चार पहिया ऐसे करोड़ों वाहन हैं जो ई-10 पेट्रोल के लिए भी तैयार नहीं हुए हैं। मामूली मिलावट का उतना असर नहीं होता था, जितना ई-20 का होना शुरू हो गया है। जिसके कारण अब लोगों का गुस्सा पेट्रोल पंपों और सड़कों पर स्पष्ट रूप से नजर आने लगा है। सरकार यह मानने के लिए तैयार नहीं है। ई-20 पेट्रोल से गाड़ी का एवरेज कम होता है। उपभोक्ता लगातार शिकायत कर रहे हैं, कि उनके वाहन का एवरेज 5 से 8 किलोमीटर तक कम हो गया है। दो पहिया वाहनों का एवरेज कम होने से गरीब और मध्यम वर्ग को दोहरा नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक तो उन्हें मिलावटी पेट्रोल ज्यादा कीमत में खरीदना पड़ रहा है। सरकार ने जो 20 फ़ीसदी एथेनॉल मिलाया है, उसके बाद भी पेट्रोल की कीमत कम नहीं की है। उपभोक्ताओं को शुद्ध पेट्रोल और मिलावटी पेट्रोल भरवाने का कोई विकल्प पेट्रोल पंपों पर नहीं दिया गया। ज्यादा पैसे चुकाने के बाद कम एवरेज मिलने और गाड़ियां खराब होने के कारण पेट्रोल उपभोक्ताओं का गुस्सा दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है।

सरकार उपभोक्ताओं की शिकायतों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही है। सरकार के मंत्री उपभोक्ताओं के जले के ऊपर नमक छिड़क रहे हैं। सरकार जो दावा कर रही है, वह वास्तविकता के विपरीत है। इसके बाद भी पेट्रोलियम मंत्री खुलेआम यह कहते हुए नजर आते हैं कि ई-20 पेट्रोल ही लेना पड़ेगा और वह सरकार द्वारा निर्धारित दर पर ही मिलेगा। इथेनॉल की मिलावट के बाद भी उस पेट्रोल के रेट कम नहीं किए जाएंगे। रही सही कसर जब पेट्रोल पंपों से मिलावटी पेट्रोल बिक ही रहा है तो पेट्रोल पंप वाले भी इस अफरा-तफरी में अपनी ओर से भी मिलावट करने लगे हैं। पेट्रोल पंपों में अब मिलावट की जांच कर पाना भी संभव नहीं रहा। सरकार के इस रूख के कारण पेट्रोल पंप संचालकों ने भी मनमानी शुरू कर दी है। गाड़ियों के शोरूम और मैकेनिकों के यहां बड़ी संख्या में गाड़ियां मरम्मत के लिए पहुंच रही हैं। फ्यूल सिस्टम चोख हो रहे हैं। गाड़ी की टंकी खराब हो रही है। गाड़ी झटके लेकर चल रही है। उपभोक्ता लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन सरकार उन शिकायतों का निराकरण करने के स्थान पर एक तरह से वाहन चालकों और पेट्रोल उपभोक्ताओं को धमकाने में लगी हुई है। जिसके कारण अब लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है।

आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी ने भी इस मामले में जन आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। इतने बड़े पैमाने पर गुस्सा होने के बाद भी यदि सरकार इस मामले में कोई उपयुक्त निर्णय नहीं ले रही है तो यह आश्चर्य करने वाला विषय है। इससे ऐसा लगता है कि इस सरकार को जनता के गुस्से और वोट की कोई चिंता नहीं है। सरकार को विश्वास है जनता कितनी भी नाराज हो जीत तो उसी की होनी है। यही आत्मविश्वास पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बयानों में दिख रहा है। अन्यथा वह उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने की दिशा में कार्यवाही करते। मिलावटी पेट्रोल को सरकार जब स्वयं महंगी कीमत पर बेच रही है। शुद्ध पेट्रोल 167 से 170 रुपए लीटर में बेच रही है। इससे उपभोक्ताओं का गुस्सा बढ़ना स्वाभाविक है। पिछले कई वर्षों से जब कच्चे तेल का दाम कम था, पेट्रोलियम कंपनियों ने लाखों करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया, इसका कोई भी लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचा। अब पेट्रोल और डीजल के नाम पर सरकार द्वारा इथेनॉल की मिलावट कर जो लूट की तैयारी की जा रही है उसकी आम जनता के बीच में बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हो रही है। सरकार को समय रहते इस दिशा में उपयुक्त निर्णय लेने की जरूरत है।

सरकार उपभोक्ताओं की शिकायतों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही है। सरकार के मंत्री उपभोक्ताओं के जले के ऊपर नमक छिड़क रहे हैं। सरकार जो दावा कर रही है, वह वास्तविकता के विपरीत है। इसके बाद भी पेट्रोलियम मंत्री खुलेआम यह कहते हुए नजर आते हैं कि ई-20 पेट्रोल ही लेना पड़ेगा और वह सरकार द्वारा निर्धारित दर पर ही मिलेगा।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

एनटीपीसी छत्तीसगढ़ में 20,456 करोड़ का निवेश करेगी

- लारा सुपर तापीय परियोजना के तीसरे चरण के लिए बोर्ड ने दी स्वीकृति

नई दिल्ली ।

सार्वजनिक क्षेत्र की अग्रणी बिजली कंपनी एनटीपीसी ने छत्तीसगढ़ में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। कंपनी के निदेशक मंडल ने 1,600 मेगावाट क्षमता वाली लारा सुपर तापीय विद्युत परियोजना के तीसरे चरण के लिए 20,456.70 करोड़ रुपये के भारी-भरकम निवेश प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि निदेशक मंडल की 11 जुलाई को हुई बैठक में इस महत्वपूर्ण निर्णय पर मुहर लगाई गई। यह विस्तार परियोजना न केवल देश में बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, बल्कि बिजली ग्रिड में तापीय और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के बेहतर समायोजन में भी मदद करेगी। एनटीपीसी का यह निवेश देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और भविष्य के ऊर्जा परिदृश्य को मजबूत करने की कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

स्मार्टवर्क्स को पुणे में 58 करोड़ का मेगा लीज़ कॉन्ट्रैक्ट

- ब्रिटिश कंपनी को 930 से अधिक सीटें पट्टे पर दीं

नई दिल्ली ।

सह-कार्यस्थल उपलब्ध कराने वाली कंपनी स्मार्टवर्क्स कोवर्किंग स्पेसेस लिमिटेड ने पुणे में ब्रिटेन की एक प्रमुख वैश्विक कंपनी को 930 से अधिक सीटें पट्टे पर दी हैं। इस बड़े सौदे से कंपनी को आगामी पांच वर्षों में कुल 58 करोड़ रुपये की किराये से आय होने की उम्मीद है। गुरुग्राम स्थित स्मार्टवर्क्स ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि यह लीज़ समझौता ब्रिटेन की एक वैश्विक पेशेवर सेवा और प्रौद्योगिकी कंपनी की भारतीय अनुषंगी इकाई के साथ किया गया है। कंपनी ने गोपनीयता के चलते लीज़ पर सीटें लेने वाली फर्म के नाम का खुलासा नहीं किया है। स्मार्टवर्क्स के लिए यह एक महत्वपूर्ण विस्तार है, जो भारतीय कोवर्किंग बाजार में इसकी बढ़ती पैठ को दर्शाता है। यह समझौता 60 महीने यानी पांच साल की अवधि के लिए हुआ है, जिससे कंपनी को अगले पांच वर्षों में 58 करोड़ रुपये की निश्चित आय प्राप्त होगी। यह सौदा स्मार्टवर्क्स के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा और इसकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगा।

राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन तय करने की प्रक्रिया शुरू

- अब राज्य नहीं दे पाएंगे इससे कम वेतन

नई दिल्ली।

श्रम मंत्रालय ने सांविधिक राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन (फ्लोर वेज) तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जानकारों के मुताबिक वेतन संहिता के अंतर्गत न्यूनतम वेतन तय किया जाएगा। अधिकारियों का समूह गणना के तरीके और खपत बास्केट पर काम कर रहा है और केंद्र सरकार 'केंद्रीय सलाहकार बोर्ड' (सीएबी) बनाएगी। सीएबी राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतन की सिफारिश करने से पहले बातचीत करेगा। यह एक बार अधिसूचित होने के बाद न्यूनतम सीमा के लिए कानूनी बाध्यता होगी और राज्य व केंद्र शासित प्रदेश इस निर्धारित सीमा से कम वेतन तय नहीं कर पाएंगे। लोगों ने बताया कि यह तकनीकी प्रक्रिया एस. पी. विशेषज्ञ समूह के तैयार अनुमानों पर आधारित होगी। इस क्रम में खपत बास्केट को नए सिरे से बनाने के बजाए महंगाई के हिसाब से संशोधित किए जाने की संभावना है। अधिकारियों का समूह तरीके की जांच कर रहा है और खपत बास्केट को अपडेट कर रहा है, जबकि केंद्रीय सलाहकार बोर्ड केंद्र को अपनी सिफारिश देने से पहले प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करेगा। मामले की जानकारी रखने वाले वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इसके साथ ही राज्यों के साथ भी बातचीत चल रही है।

रुपया गिरावट पर बंद

मुंबई ।

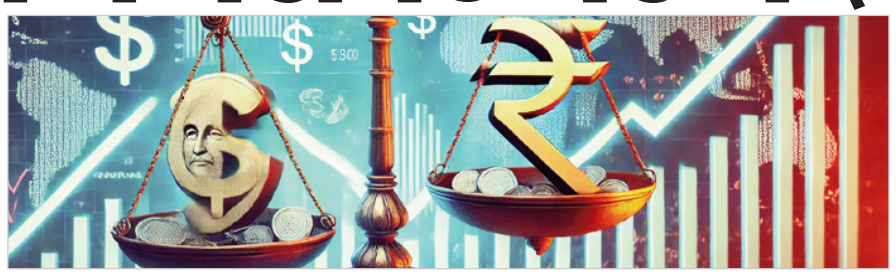

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सोमवार को रुपये में गिरवट रही और ये 26 पैसे टूटकर 95.64 पर बंद हुआ। सोमवार सुबह कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बीच रुपया सोमवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 39 पैसे टूटकर 95.77 प्रति डॉलर पर आ गया। वहीं विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार, ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने की घोषणा के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमत 79 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई, जिससे रुपये पर दबाव बढ़ा। उन्होंने कहा कि घरेलू मुद्रा के कमजोर शुरुआत के साथ 95.53 प्रति डॉलर के स्तर पर खुलने की उम्मीद थी। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 95.72 प्रति डॉलर पर खुला और बाद में 95.77 प्रति डॉलर के स्तर तक गिर गया। यह पिछले बंद भाव के मुकाबले 39 पैसे की गिरावट है। वहीं रुपया शुक्रवार को अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले नौ पैसे मजबूत होकर 95.38 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था।

इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती को दिखाने वाला डॉलर सूचकांक 0.17 फीसदी बढ़कर 101.12 पर कारोबार कर रहा था।

एचडीएफसी बैंक ने अपने कर्मचारियों की संख्या 3,343 घटाई

नई दिल्ली ।

वित्त वर्ष 2025-26 में एचडीएफसी बैंक ने अपने कर्मचारियों की संख्या 3,343 घटा दी है। अब उसके कर्मचारियों की संख्या घटकर 2.11 लाख रह गई है। पिछले नौ वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है क्योंकि देश का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक प्रौद्योगिकी के उपयोग और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के विकास में तेजी से अपनी भागीदारी बढ़ा रहा है। इससे पहले ऐक्सिस बैंक ने प्रौद्योगिकी में अपने निवेश के कारण उत्पादकता में हुए सुधार को देखते हुए वित्त वर्ष 2026 में कर्मचारियों की संख्या में करीब 3,100 की कटौती की थी। एचडीएफसी बैंक के एक अे धिकारी ने नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में शेयरधारकों से कहा` कि प्रौद्योगिकी से संचालित और ग्राहक केंद्रित बैंक बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने के साथ ही हमें कर्मचारियों के साथ बेहतर तालमेल बिठाने की आवश्यकता है। हम अपने लोगों को प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर अधिक उत्पादक तरीके से और ग्राहकों की जरूरतों के हिसाब से काम करने में सक्षम बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

सेवानिवृत्ति की तैयारी ईपीएफ, पीपीएफ या एनपीएस कौन है बेहतर विकल्प?

- बढ़ती महंगाई और लंबी जीवन प्रत्याशा के बीच वित्तीय सुरक्षा के लिए तीनों योजनाओं को समझना जरूरी

नई दिल्ली ।

बढ़ती महंगाई और लंबी जीवन प्रत्याशा को देखते हुए, सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। केवल बचत पर्याप्त नहीं, बल्कि नियमित आय देने वाली निवेश योजनाएं आवश्यक हैं। भारत में कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) तीन प्रमुख विकल्प हैं, जिनके नियम, जोखिम, रिटर्न और कर लाभ भिन्न हैं। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ईपीएफ एक मजबूत आधार है, जहां नियोक्ता-कर्मचारी योगदान से बड़ा फंड बनता है। सरकारी ब्याज दर के साथ यह नौकरीपेशा लोगों के लिए सुरक्षित बचत है।

वहीं पीपीएफ किसी भी भारतीय नागरिक के लिए सुरक्षित और सरकारी गारंटी वाली योजना है। 7.1 फीसदी ब्याज दे रही यह योजना, निवेश, ब्याज और परिपक्वता राशि पर कर छूट (ईईई) के कारण दीर्घकालिक निवेश का लोकप्रिय विकल्प है। एनपीएस अधिक रिटर्न चाहने वाले और सीमित बाजार जोखिम उठाने को तैयार निवेशकों के लिए बेहतर है। यह शेयर, बॉन्ड आदि में निवेश करती है, बाजार-आधारित प्रतिफल के साथ अतिरिक्त कर लाभ देती है। वित्तीय विशेषज्ञ तीनों योजनाओं के संतुलित संयोजन की सलाह देते हैं ताकि सुरक्षा, कर बचत और बेहतर रिटर्न का लाभ मिल सके। नियमित निवेश और योजना की समीक्षा भविष्य की वित्तीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

शेयर बाजार हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ

सेंसेक्स 47अंक , निफ्टी 4 अंक उछला

मुंबई ।

भारतीय शेयर बाजार सोमवार को हल्की बढ़त पर बंद हुआ। आज दुनिया भर के बाजारों से मिले नकारात्मक वैश्विक संकेतों के साथ ही उतार-चढ़ाव जारी रहने से बाजार में उत्साह नहीं था। । सप्ताह के पहले ही कारोबारी दिन आईटी शेयरों में तेजी से बाजार अंत में बढ़त पर बंद हुआ। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 47.01 अंक उछलकर 77,616.40 पर जबकि 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 4.10 अंक बढ़कर 24,211 पर बंद हुआ। वहीं व्यापक बाजार में, निफ्टी मिडकैप और निफ्टी स्मॉलकैप भी हल्की तेजी के साथ बंद हुआ। आज सेक्टरवार देखें तो निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी मेटल में सबसे ज्यादा गिरावट रही जबकि निफ्टी आईटी में सबसे ज्यादा तेजी आई । इसके बाद निफ्टी मीडिया और निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी बढ़त रही। निफ्टी ऑटो में और निफ्टी प्राइवेट बैंक व निफ्टी पीएसयू बैंक में भी तेजी रही।वहीं इसके विपरीत, निफ्टी एफएमसीजी में गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा निफ्टी मेटल , निफ्टी इंफ्रा और निफ्टी रियल्टी में गिरावट आई। निफ्टी फार्मा और निफ्टी एनर्जी भी नीचे आये। निफ्टी में टीसीएस और एचसीएलटेक में बढ़त दर्ज की गई और ये दिन के सबसे अधिक लाभ वाले शेयर रहे। टेक महिंद्रा, इंफोसिस, बजाज ऑटो और एनटीपीसी के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। जबकि, सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले शेयरों में ग्रासिम इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील, नेस्ले इंडिया के शेयर रहे ।जानकारों के अनुसार अमेरिका द्वारा ईरान पर हमले बढ़ाने के बाद से ही ब्रेंट क्रूड की कीमतों में 3 तेजी आई है जिससे बाजार पर दबाव आया है।

।वहीं इससे पहले आज सुबह शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों प्रमुख सूचकांकों में तेज गिरावट दर्ज की गई। सुबह शुरुआत के बाद निफ्टी 50 178 अंक की गिरावट के साथ 24,029.75 पर कारोबार कर रहा था।

एयरटेल का डिजिटल महाविस्तार,वित्तीय सेवाओं और डेटा केंद्रों पर दांव

चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने वार्षिक रिपोर्ट में किया खुलासा

नई दिल्ली ।

दूरसंचार क्षेत्र की अग्रणी कंपनी भारती एयरटेल अब सिर्फ मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं तक सीमित नहीं रहना चाहती। चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में घोषणा की है कि एयरटेल भविष्य में वित्तीय सेवाओं, डाटा केंद्र और क्लाउड कारोबार को अपनी अगली विकास यात्रा का प्रमुख आधार बनाएगी। यह रणनीतिक विस्तार भारत में तेजी से बढ़ते डिजिटलीकरण और क्लाउड सेवाओं की मांग का लाभ उठाने के लिए तैयार किया गया है। मित्तल ने बताया कि एयरटेल मनी में लगभग 20 हजार करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना है, जिसे आरबीआई से गैर-जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में मंजूरी मिल चुकी है। यह कदम देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगा। इसके साथ ही कंपनी अपने डाटा केंद्र कारोबार एनएक्स्ट्रा का भी तेजी से विस्तार कर रही है, जिसके तहत 1000 मेगावाट क्षमता वाले डाटा केंद्र विकसित करने का लक्ष्य है। हाल ही में एनएक्स्ट्रा के लिए लगभग एक अरब अमेरिकी डॉलर की राशि जुटाई गई है, जो क्लाउड सेवाओं की बढ़ती मांग और डेटा को भारत में सुरक्षित रखने की जरूरत को पूरा करेगी। पिछले एक दशक में भारती एयरटेल ने डिजिटल बुनियादी ढांचे पर 3.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है, जो इस नए विस्तार का आधार बनेगा।

भारत-ब्रिटेन एफटीए लागू- व्यापार को नई गति, पेशेवरों को बड़ा लाभ

- 15 जुलाई से निर्यात शुल्क शून्य

नई दिल्ली ।

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) 15 जुलाई से लागू होगा। यह निर्यातकों को शून्य शुल्क का लाभ देगा और ब्रिटेन में कार्यरत भारतीय पेशेवरों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा। इस समझौते के तहत ब्रिटेन को भेजे जाने वाले सभी भारतीय उत्पादों पर कोई आयात शुल्क नहीं लगेगा, जिससे किसानों, मछुआरों और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) जैसे क्षेत्रों को सीधा फायदा होगा। गोयल ने बताया कि यह समझौता ब्रिटेन में काम करने वाले भारतीय पेशेवरों के लिए भी बड़ा बदलाव लाएगा।

डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन (डीसीसी) के तहत, पांच साल तक ब्रिटेन में कार्यरत भारतीयों को अब वहां सामाजिक सुरक्षा में योगदान नहीं देना होगा। इसके बजाय, उनके वेतन का लगभग 25 फीसदी सीधे भारत में उनके भविष्य निधि खातों में 8.25 फीसदी कर-मुक्त ब्याज के साथ जमा होगा। गोयल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को दिया।

सरकारी बैंकों का बड़ा कदम, 15,000 एटीएम बनेंगे स्मार्ट मिनी बैंक

तेज, सुरक्षित और मल्टी-सर्विस सुविधा से बैंकिंग होगी आसान, 24म7 बैंकिंग का नया अनुभव

नई दिल्ली ।

देश के सरकारी बैंकों ने ग्राहकों की सुविधाएं बढ़ाने और डिजिटल बैंकिंग को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 15,000 पुराने एटीएम को नई तकनीक से अपग्रेड किया जाएगा। इन नए एटीएम को स्मार्ट, तेज और सुरक्षित बनाया जाएगा, जिनका लक्ष्य सिर्फ पैसे निकालने की मशीन से बदलकर एक छोटी बैंक शाखा का रूप देना है। यह अपग्रेड होने के बाद एटीएम से ग्राहकों को कई नई सुविधाएं मिलेंगी। इनमें कैश रीसाइक्लिंग मशीन सबसे अहम होगी, जिससे ग्राहक पैसे निकालने के साथ-साथ जमा भी कर सकेंगे। इसके अलावा, बिना डेबिट कार्ड के यूपीआई आधारित कैश निकासी की सुविधा भी मिलेगी। नई मशीनों में बेहतर सिक्योरिटी फीचर्स जोड़े जाएंगे, जिससे ऑनलाइन और एटीएम फ्रॉड से सुरक्षा बढ़ेगी और ट्रांजैक्शन तेजी से होंगे। बैलेंस चेक और मिनी स्टेटमेंट जैसी मल्टी-सर्विस भी एक ही जगह उपलब्ध होगी। इस बदलाव का सबसे ज़्यादा फायदा उन लोगों को मिलेगा जहां बैंक शाखाएं कम हैं, जैसे ग्रामीण और छोटे शहर। करोड़ों सरकारी बैंक ग्राहकों के लिए 24 इनटू 7 बैंकिंग आसान हो जाएगी, जिससे छोटी-मोटी

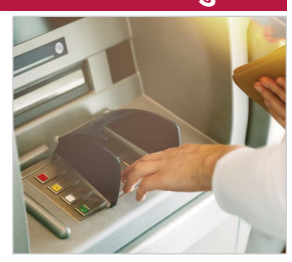

जरूरतों के लिए बैंक शाखा जाने की आवश्यकता कम होगी। इससे बैंक की लागत में भी कमी आने की उम्मीद है।

इस सप्ताह निवेशक तीन नए आईपीओ में निवेश कर सकेंगे

- निवेशकों के पास 10 हजार करोड़ से अधिक के इश्यू में निवेश का मौका

नई दिल्ली ।

इस सप्ताह शेयर बाजार में निवेशकों के सामने तीन नए आईपीओ में निवेश का अवसर होगा, जिनका कुल आकार 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक है। इनमें एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट, अल्पाइन टेक्सवर्ल्ड और मिलवर्क्स टेक्नोलॉजी के आईपीओ शामिल हैं। पहले दो इश्यू मेनबोर्ड श्रेणी के हैं, जबकि मिलवर्क्स टेक्नोलॉजी का आईपीओ एसएमई प्लेटफॉर्म पर आएगा। निवेशक अपनी रणनीति और जोखिम क्षमता के अनुसार इनमें से किसी एक या सभी इश्यू में आवेदन कर सकते हैं। इस सप्ताह का सबसे बड़ा आईपीओ एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का है। भारतीय स्टेट बैंक और फ्रांस की परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी अमुंडी के संयुक्त उपक्रम की यह कंपनी आईपीओ के माध्यम से 9,812.91 करोड़ रुपये जुटाने जा रही है। इसके लिए प्रति शेयर 545 से 574 रुपये का प्राइस बैंड तय किया गया है। यह ऑफर फॉर सेल आधारित इश्यू है, इसलिए इससे प्राप्त राशि कंपनी के बजाय अपने शेयर बेच रहे प्रवर्तकों को मिलेगी। इस इश्यू के तहत भारतीय स्टेट बैंक लगभग 4.88 प्रतिशत और अमुंडी करीब 3.51 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेंगे। दूसरा मेनबोर्ड आईपीओ गुजरात की टेक्सटाइल कंपनी अल्पाइन टेक्सवर्ल्ड का है। कंपनी 126.25 करोड़ रुपये जुटाएगी और इसके लिए 100 से 105 रुपये प्रति शेयर का मूल्य दायरा निर्धारित किया गया है। यह पूरी तरह फ्रेश इश्यू है। आईपीओ से प्राप्त धनराशि का उपयोग नया वीविंग प्लांट स्थापित करने, ग्रे फैब्रिक उत्पादन क्षमता बढ़ाने, कर्ज चुकाने तथा अन्य कारोबारी जरूरतों को पूरा करने में किया जाएगा। एसएमई श्रेणी में बेंगलुरु की प्रिसिजन इंजीनियरिंग कंपनी मिलवर्क्स टेक्नोलॉजी 160.30 करोड़ रुपये का आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी ने 315 से 331 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। इस इश्यू से मिलने वाली राशि नई मशीनों की खरीद, कार्यशील पूंजी और सामान्य व्यावसायिक जरूरतों पर खर्च की जाएगी।

इस वर्ष अब तक 30 मेनबोर्ड आईपीओ के जरिए 24,404 करोड़ रुपये जुटाए जा चुके हैं। नए इश्यू के बाद यह आंकड़ा 34,343 करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है। वहीं एसएमई प्लेटफॉर्म पर अब तक 90 कंपनियां 3,861 करोड़ रुपये जुटा चुकी हैं।

अमेरिका-ईरान टकराव के बीच ब्रेंट 79 डॉलर के पार

नई दिल्ली ।

पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने का असर कच्चे तेल की कीमतों पर देखने को मिला है। सोमवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल करीब 4 फीसदी उछल गया। ब्रेंट क्रूड 79 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया, जबकि अमेरिकी डब्ल्यूटीआई क्रूड 74 डॉलर प्रति बैरल के पार कारोबार करता दिखा। हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम शांति समझौते के बाद तेल की कीमतों में कुछ गिरावट आई थी। लेकिन नए सैन्य तनाव ने उस राहत को खत्म कर दिया।

अब दोनों देशों के बीच बातचीत की संभावना भी कमजोर पड़ गई है। ईरान ने कहा है कि बातचीत आगे बढ़ाने से पहले होर्मुज जलडमरूमध्य और तेल निर्यात से जुड़े मुद्दों पर प्रगति जरूरी है। सोमवार सुबह ब्रेंट क्रूड करीब 3.93 फीसदी बढ़कर 79 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। वहीं अमेरिकी डब्ल्यूटीआई क्रूड भी करीब 3.98 फीसदी की तेजी के साथ 74.25 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार करता दिखा। दूसरी ओर, अमेरिकी प्राकृतिक गैस की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। अमेरिका में प्राकृतिक गैस की कीमतें गिरकर 2.90 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू पर आ गई हैं, जो पिछले सात हफ्तों का सबसे निचला स्तर है। इसकी मुख्य वजह आने वाले दिनों में मौसम के ठंडा रहने का अनुमान है, जिससे एयर कंडीशनिंग की मांग घट सकती है और गैस से बनने वाली बिजली की खपत कम होने की उम्मीद है। इसके अलावा, फ्रीपोर्ट एलएनजी ने 10 जुलाई से अगस्त के आखिर तक अपने प्लांट में रखरखाव (मेंटेनेंस) का काम शुरू किया है, जिससे अस्थायी रूप से गैस की खपत घटेगी। वहीं अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन के ताजा आंकड़ों के अनुसार 3 जुलाई तक देश में प्राकृतिक गैस का भंडार पिछले पांच साल के औसत से 6.6 फीसदी अधिक है।

कीस्टोन रियल्टर्स की बिक्री बुकिंग में 42 फीसदी की गिरावट

वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 617 करोड़ रुपये रही बिक्री बुकिंग

नई दिल्ली ।

रियल एस्टेट फर्म कीस्टोन रियल्टर्स लिमिटेड को वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-जून तिमाही में बिक्री बुकिंग में 42 फीसदी की उल्लेखनीय गिरावट का सामना करना पड़ा है। इस तिमाही में कंपनी की बिक्री बुकिंग 617 करोड़ रुपये दर्ज की गई, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2025-26 की समान अवधि में यह 1,068 करोड़ रुपये थी। मुंबई स्थित इस कंपनी ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के लिए अपने तिमाही कारोबारी प्रदर्शन की जानकारी साझा की है। कंपनी ने बताया कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कोई नई परियोजना शुरू नहीं की गई। ऐसे में बिक्री मुख्य रूप से मौजूदा परियोजनाओं की स्थिर मांग और खरीदारों के भरोसे से समर्थित रही। हालांकि, कंपनी को ग्राहकों से प्राप्त राशि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में बढ़कर 599 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले 575 करोड़ रुपये थी। कीस्टोन रियल्टर्स के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक बोमन ईरानी ने इसे स्थिर शुरुआत बताते हुए कहा कि वे पिछली गति को बनाए रखेंगे। कंपनी को वैश्विक स्थिरता से आर्थिक सुधार और आगामी तिमाहियों में बिक्री बढ़ने की उम्मीद है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

यूपी टी20 सीजन चार का शेड्यूल आया सामने, पहली बार दो शहरों में होस्ट की जाएगी लीग

कानपुर (एजेंसी)। यूपी टी20 लीग (यूपी टी 20 सीजन 4) 14 अगस्त से 6 सितंबर तक होगी। 24 दिन के इस टूर्नामेंट में 34 मैच होंगे, जिसमें 13 डबल हेडर मैचडे और 8 सिंगल-हेडर मैचडे शामिल हैं, ऑर्गनाइजर ने रविवार को यह घोषणा की। लीग के इतिहास में पहली बार यूपी टी20 को 2 शहरों में होस्ट किया जाएगा। टूर्नामेंट का पहला फेज भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ में खेला जाएगा, जहां 13 मैचडे में 22 मैच होंगे।

दूसरा फेज ग्रीन पार्क स्टेडियम, कानपुर में शिफ्ट होगा, जहां 11 मैचडे में बाकी 12 मैच होस्ट किए जाएंगे। यूपी टी20 सीजन 4 की ओपनिंग सेरेमनी और पहला मैच लखनऊ में होगा, जबकि कानपुर में फाइनल और क्लोजिंग सेरेमनी होगी, जिससे टूर्नामेंट का शानदार समापन होगा। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की गवर्निंग काउंसिल की रविवार को मीटिंग हुई और यूपी टी 20 लीग के चौथे एडिशन के आयोजन से जुड़े कई खास प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

इस मौके पर, यूपीसीए ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ और बीसीसीआई के उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद, राजीव शुक्ला का खेलों के विकास के लिए लगातार गाइडेंस, सपोट और कमिटमेंट के लिए दिल से शुक्रिया अदा किया। गवर्निंग

काउंसिल ने टूर्नामेंट के शेड्यूल, जगहों, प्लेयर ऑक्शन, टूर्नामेंट ऑपरेशन, टैलेंट डेवलपमेंट और कॉम्पिटिशन की दूसरी खास बातों पर भी डिटेल में बातचीत की।

यूपी टी20 सीजन 4 का मिनी ऑक्शन 24 जुलाई को आगरा में होगा, जिसमें लीग की छह फ्रेंचाइजी में 45 प्लेयर स्लॉट उपलब्ध होंगे। इसके अलावा गवर्निंग काउंसिल ने रिटेंशन पॉलिसी, प्लेयर सिलेक्शन प्रोसेस, कैचमेंट एरिया ट्रायल्स, सपोर्ट स्टाफ सिलेक्शन गाइडलाइंस और मिनी ऑक्शन रेगुलेशन को मंजूरी दी, जिससे पूरे टूर्नामेंट में ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और हाई प्रोफेशनल स्टैंर्ड सुनिश्चित होंगे। लोकल टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए, कैचमेंट एरिया मॉडल लागू रहेगा, जिससे उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों के उभरते हुए क्रिकेटरों को अपनी स्किल्स दिखाने के ज्यादा मौके मिलेंगे। भारत के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना यूपी टी20 लीग के ब्रांड एंबेसडर बने रहेंगे। लीग का पॉपुलर ऑफिशियल एंथम, खिलाड़ी यहां बनता है (चैंपियंस यहां बनते हैं), इस सीजन में भी जारी रहेगा। शानदार परफॉर्मेंस को इनाम देने के लिए लीग ने कुल 3 करोड़ रुपए का प्राइज पूल रखा है। चैंपियन को 1 करोड़ रुपए, रनर-अप को 60 लाख रुपए मिलेंगे जबकि दूसरी टॉप परफॉर्म करने वाली टीमों और खिलाड़ियों को भी आकर्षक कैश अवॉर्ड मिलेंगे।

हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने छोड़ा सीएसके का साथ

18 साल बाद अलग हुए, कहा- टीम हमेशा दिल के करीब रहेगी, 5 आईपीएल टाइटल जिताए

चेन्नई (एजेंसी)। आईपीएल की सबसे सफल टीम चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) और उसके हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग का 18 साल पुराना साथ खत्म हो गया। फ्रेंचाइजी ने सोमवार को सोशल पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। सीएसके ने एक्स पर लिखा- 'हमने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है। हमने आईपीएल इतिहास की सबसे सफल और लंबे समय तक चलने वाली पार्टनरशिप में से एक को साझा किया है। आपने जो विरासत बनाई है, वह हमें प्रेरित करती रहेगी। बेहद सम्मान और आभार के साथ, धन्यवाद स्टीफन।' न्यूजीलैंड के स्टीफन फ्लेमिंग आईपीएल के पहले सीजन में बतौर खिलाड़ी चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़े थे। 2009 में उन्होंने कोचिंग की जिम्मेदारी संभाली और 2010 में पहला टाइटल जिता दिया।

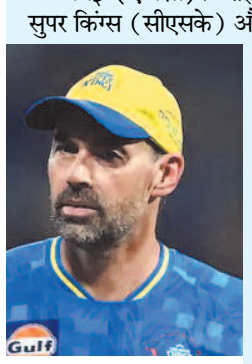

आईपीएल के सबसे सफल कोच हैं फ्लेमिंग

फ्लेमिंग की रणनीति, शांत नेतृत्व और खिलाड़ियों पर भरोसा सीएसके की पहचान बन गया। उनकी और एमएस धोनी की जोड़ी को आईपीएल इतिहास की सबसे सफल कोच-कप्तान जोड़ियों में गिना जाता है।

फ्लेमिंग ने कहा-18 साल खेल में एक पूरी जिंदगी के बराबर होते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के साथ बिताया समय मेरे कोचिंग करियर का सबसे बड़ा सम्मान रहा। हमने साथ मिलकर यादगार जीत हासिल कीं। मुश्किल दौर देखे और ऐसी यादें बनाईं जो हमेशा मेरे साथ रहेंगी। फ्रेंचाइजी हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगी। मैं आगे भी टीम को सपोर्ट करता रहूंगा।

सिनर ने लगातार दूसरी बार विंबलडन जीता

- ज्वेरेव को चार सेट में हराया ; युवराज सिंह, अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी मैच देखने पहुंचे

लंदन (एजेंसी)। वर्ल्ड नंबर-1 टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर ने विंबलडन 2026 का पुरुष एकल खिताब अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ 24 वर्षीय सिनर लगातार दूसरी बार विंबलडन चैंपियन बने। वे ओपन एरा में विंबलडन पुरुष एकल खिताब बचाने वाले इतिहास के सिर्फ 10वें खिलाड़ी बन गए। 24 साल के सिनर ने पहली बार फाइनल खेल रहे में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 6-7(7), 7-6(2), 6-3, 6-4 से हराकर लगातार दूसरी बार ट्रॉफी जीती। यह मैच 3 घंटे 46 मिनट तक चला। इसी के साथ सिनर ने करियर का 100वां ग्रैंड स्लैम मैच जीतने की अचीवमेंट भी हासिल की। चैंपियन बनने पर सिनर को 36 लाख पाउंड (करीब 42 करोड़) की इनामी राशि भी मिली। वे एटीपी रैंकिंग में नंबर-1 बने रहेंगे। उनके और नए नंबर-2 बनने वाले ज्वेरेव के बीच 4,970 अंकों का अंतर रहेगा।

यह 5वां ग्रैंड स्लैम टाइटल, इस साल पहला

यह सिनर के करियर का 5वां ग्रैंड स्लैम और 2026 सीजन का पहला मेजर खिताब है। इससे पहले वे फ्रेंच ओपन के दूसरे दौर में जुआन मैनुअल सेरुंडोलो से हारकर बाहर हो गए थे। हालांकि, उन्होंने ग्रास कोर्ट पर शानदार वापसी की। सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में हराने के बाद फाइनल में भी उन्होंने दमदार प्रदर्शन किया।

स्मृति मंधाना का लॉर्ड्स में चला बल्ला

- लगाया दूसरा अर्धशतक ; दूसरी पारी में भी शतक लगाने से चूकीं

नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ओपनर बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच की सीरीज की दूसरी पारी में भी अपने बल्ले का दम दिखाया और इस बार भी वो शतक लगाने से चूक गईं। स्मृति मंधाना पहली पारी में भी शतक के करीब पहुंच गई थीं, लेकिन वो लॉर्ड्स में शतक नहीं लगा पाईं। दूसरी पारी में भी उनके पास मौका था जो उनके हाथ से निकल गया। हालांकि मंधाना टेस्ट क्रिकेट में दोनों पारियों में 70 रन ये उससे ज्यादा रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बनीं।

भारत ने लॉर्ड्स का पहला महिला टेस्ट जीता

इंग्लैंड को 270 रन से हराया, यस्तिका का शतक, मंधाना ने दोनों पारियों में फिफ्टी लगाई

लंदन (एजेंसी)। भारत ने लॉर्ड्स में खेले गए पहले महिला टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया। भारत ने इंग्लैंड को 457 रन का टारगेट दिया था, लेकिन चौथे दिन टीम दूसरी पारी में 186 रन पर सिमट गई। भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए थे। जवाब में इंग्लैंड की टीम 170 रन पर ऑलआउट हो गई और भारत को 115 रन की बढ़त मिली। इसके बाद दूसरी पारी में भारत ने 341/7 पर घोषित कर इंग्लैंड को 457 रन का टारगेट दिया। दूसरी पारी में यस्तिका भाटिया ने 113 रन की पारी खेली। वहीं स्मृति मंधाना ने 70 रन बनाए। स्मृति ने पहली पारी में भी 83 रन बनाए थे। ऋचा घोष ने भी नाबाद 50 रन बनाकर टीम को मजबूत बढ़त दिलाई।

पहली पारी में क्रांति ने 5 विकेट लिए - इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही और शेफाली वर्मा बिना

खाता खोले आउट हो गईं। इसके बाद स्मृति मंधाना (83), कप्तान हरमनप्रीत कौर (58) और दीप्ति शर्मा (57) की पारियों से भारत ने 285 रन बनाए। इंग्लैंड की ओर से सोफी एक्लेस्टोन और लॉरेन फिलर ने 2-2 विकेट लिए।

जवाब में इंग्लैंड की पहली पारी 170 रन पर सिमट गई। क्रांति गौड़ ने 5 विकेट झटके। सयाली सतघारे और स्नेह राणा ने 2-2 विकेट लिए, जबकि दीप्ति शर्मा को एक सफलता मिली। एमी जोन्स ने 52 और कप्तान नेट सिवर-ब्रंट ने 44 रन बनाए, लेकिन बाकी बल्लेबाज टिक नहीं सके।

यस्तिका ने रचा इतिहास, भारत ने मैच पर कब्जा जमाया - 115 रन की बढ़त के साथ दूसरी पारी खेलने उतरी भारतीय टीम को स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने 88 रन की शुरुआत दी। इसके बाद यस्तिका भाटिया ने जिम्मेदारी संभालते हुए 113 रन की बेहतरीन पारी खेली। उन्होंने स्मृति के साथ 73 और दीप्ति शर्मा के साथ 52 रन की साझेदारी की। ऋचा घोष ने नाबाद 50 और सयाली सतघारे ने नाबाद 18 रन बनाकर भारत को 341/7 तक पहुंचाया। इंग्लैंड की स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन ने 5 विकेट लिए, लेकिन भारत ने 456 रन की बढ़त हासिल कर ली।

चौथे दिन भारतीय स्पिनरों ने खत्म किया मुकाबला - 457 रन का पीछा करते हुए इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। टैमी ब्यूमोंट, माया बुशियर, हीदर नाइट और कप्तान नेट-ब्रंट जल्दी आउट हो गईं। एमी जोन्स ने 54 और सोफी एक्लेस्टोन ने 50 रन बनाकर संघर्ष किया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने इंग्लैंड ज्यादा देर टिक नहीं सका। स्नेह राणा ने 4 विकेट लिए। सयाली सतघारे, क्रांति गौड़ और दीप्ति शर्मा ने 2-2 विकेट लिए। इंग्लैंड की पूरी टीम 186 रन पर सिमट गई और भारत ने मुकाबला 270 रन से जीत लिया।

राहुल द्रविड़ बन सकते हैं इंग्लैंड टेस्ट टीम के कोच

एंडी फ्लावर, फ्लिंटॉफ और लैंगर के नाम पर भी चर्चा; मैकुलम को हटाया

लंदन (एजेंसी)। टीम इंडिया के पूर्व कोच राहुल द्रविड़ इंग्लैंड की टेस्ट टीम के नए मुख्य कोच बनने की दौड़ में शामिल हैं। ब्रेंडन मैकुलम के पद छोड़ने के बाद ईसीबी (इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड) पॉसिबल कैंडीडेट्स के नाम पर विचार कर रहा है, जिसमें द्रविड़ का नाम भी है।

डेली टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार द्रविड़ उन चुनिंदा कैंडीडेट्स में शामिल हैं, जिन पर ईसीबी विचार कर रहा है। इस लिस्ट में एंडी फ्लावर, एंड्रयू फ्लिंटॉफ और जस्टिन लैंगर जैसे नाम शामिल हैं। एक दिन पहले रविवार 12 जुलाई को ईसीबी ने मैकुलम को टेस्ट कोच के पद हटाने की जानकारी दी।

द्रविड़ की कोचिंग स्ट्राइल बनी बड़ी ताकत - द्रविड़ की प्लांड कोचिंग, खिलाड़ियों को विकसित करने की क्षमता और लंबे समय की सोच उन्हें इस पद के लिए मजबूत दावेदार बनाती है। 53 साल द्रविड़ के कार्यकाल में भारत ने 2024

टी-20 वर्ल्ड कप जीता था। टीम 2023 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी पहुंची थी। भारत की अंडर-19 और ए टीम के साथ उनका काम भी काफी सराहा गया है।

फुल-टाइम कोचिंग के इच्छुक नहीं हैं द्रविड़ - रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि द्रविड़ फुलटाइम कोचिंग की जिम्मेदारी लेने के इच्छुक नहीं हैं। इंग्लैंड की टेस्ट टीम का कोच बनने पर उन्हें परिवार के साथ अधिक समय बिताने का मौका मिलेगा और टेस्ट क्रिकेट में योगदान देने का अवसर भी मिलेगा। इसलिए ईसीबी कम से कम उनकी रुचि जरूर जानना चाहेगा।

- एंडी फ्लावर सबसे मजबूत दावेदार - पूर्व जिम्बाब्वे कप्तान एंडी फ्लावर भी इस पद के प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। उनके कार्यकाल में इंग्लैंड ने तीन एशेज सीरीज जीती थीं। साथ ही टेस्ट रैंकिंग में नंबर-1 स्थान हासिल किया था। रिचर्ड डॉसन, श्रीलंका के महान बल्लेबाज कुमार संगकारा और पाकिस्तान के मुख्य कोच माइक हेसन के नाम भी संभावित उम्मीदवारों में शामिल बताए जा रहे हैं। ईसीबी अगले साल होने वाली एशेज सीरीज को ध्यान में रखते हुए जल्द ही नए टेस्ट मुख्य कोच की नियुक्ति करना चाहता है।

अदिति अशोक एवियन चैंपियनशिप में संयुक्त 56वें स्थान पर पहुंची

एवियन ले बेंस (फ्रांस) (एजेंसी)। भारतीय गोल्फर अदिति अशोक अंतिम दौर में तीन ओवर 74 के लचर प्रदर्शन के साथ रविवार को यहां 2026 आमुंडी एवियन चैंपियनशिप में संयुक्त रूप से 56वें स्थान पर रहीं।

दक्षिण कोरिया की हेइ रेन रयु ने पहले प्ले ऑफ में बर्डी पट के साथ लगातार दूसरा मेजर खिताब अपने नाम किया। शुरुआती तीन दौर में 70, 70 और 69 के स्कोर के साथ अदिति के पास अच्छा नतीजा हासिल करने का मौका था लेकिन वह अंतिम होल में पांच बोगी और दो बर्डी से तीन ओवर का स्कोर ही बना पाईं। दो हफ्ते पहले 2026 केपीएमजी महिला पीजीए चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले रयु ने प्ले ऑफ में कनाडा की ब्रूक हेंडरसन को पछाड़ा। रयु ने इसी गोल्फ कोर्स पर 2015 में आमुंडी एवियन जूनियर्स कप भी जीता था।

फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप

सेमीफाइनल में 35 साल बाद सभी पूर्व चैंपियंस

अर्जेंटीना-इंग्लैंड की 40 साल पुरानी राइवलरी, एम्बाप्पे का फ्रांस यमाल के स्पेन से खेलेगा

अटलांटा (एजेंसी)। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। फुटबॉल की चार दिग्गज टीमें- अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन ने टॉप-4 में प्रवेश किया है। 1990 के बाद यह पहला मौका है, जब वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में सिर्फ पूर्व चैंपियन टीमें पहुंची हैं। एक खास बात और है, ये चारों टीमें फीफा रैंकिंग में टॉप-4 में शामिल हैं। ऐसा पहली बार हुआ है, जब रैंकिंग की टॉप-4 टीमों सेमीफाइनल में पहुंची हैं और खिताब से सिर्फ दो जीत दूर हैं। मंगलवार को किलियन एम्बाप्पे की फ्रांस और लामिन यमाल के स्पेन आमने-सामने होंगे, जबकि बुधवार को लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना और हैरी केन की इंग्लैंड के बीच मैच खेला जाएगा।

अर्जेंटीना - इंग्लैंड - अर्जेंटीना और इंग्लैंड की भिड़ंत सिर्फ फुटबॉल तक सीमित नहीं रही है। 1982 के फॉकलैंड युद्ध से लेकर वर्ल्ड कप के कई विवादित मुकाबलों तक दोनों देशों की राइवलरी काफी पुरानी है।1986 वर्ल्ड कप में डिएगो माराडोना के चर्चित हैंड ऑफ गॉड गोल की बदौलत अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को हराया था। 1998 में डेविड बेकहम को रेड कार्ड मिला और अर्जेंटीना ने पेनल्टी शूटआउट में जीत दर्ज की।2002 में बेकहम ने पेनल्टी गोल कर इंग्लैंड को जीत दिलाई थी। अब मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना लगातार दूसरा खिताब जीतने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगा।

स्पेन - फ्रांस - दूसरे सेमीफाइनल में फ्रांस और स्पेन की टक्कर होगी। दोनों टीमें 2 साल पहले यूरोपीय चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भी भिड़ी थीं, जहां स्पेन ने 2-1 से जीत दर्ज की थी। फ्रांस के पास किलियन एमबाप्पे, माइकल ओलिसे और डिजिरे डुए जैसे स्टार खिलाड़ी हैं, जबकि स्पेन की उम्मीदें युवा स्टार लामिन यामाल और मिडफील्डर मिकेल मेरिनो पर टिकी होंगी। मेरिनो ने लगातार दो नॉकआउट मुकाबलों में निर्णायक गोल कर स्पेन को जीत दिलाई है।

मेसी के पास इतिहास रचने का मौका - 39 साल लियोनेल मेसी अपने करियर का आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। उनके नाम विश्व कप इतिहास में सबसे ज्यादा 21 गोल हैं।अगर मेसी अर्जेंटीना को लगातार दूसरा वर्ल्ड कप दिलाने में सफल रहते हैं, तो वह डिएगो माराडोना के बराबर नहीं, बल्कि उनसे भी आगे निकल जाएंगे।अर्जेंटीना अगर खिताब जीतता है तो वह 1962 के बाद लगातार दो वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बनेगी। इससे पहले ब्राजील और इटली यह कारनामा कर चुके हैं।

ब्रेंडन मैकुलम की बर्खास्तगी पर भड़की इंग्लैंड की पूर्व क्रिकेटर एलेक्स, ईसीबी को लगाई फटकार

लंदन (एजेंसी)। भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में खेले जा रहे ऐतिहासिक महिला टेस्ट के दौरान इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) द्वारा ब्रेंडन मैकुलम को पुरुष टेस्ट टीम के मुख्य कोच पद से हटाने की घोषणा विवादों में आ गई है। इंग्लैंड की पूर्व क्रिकेटर एलेक्स हार्टले ने इस फैसले के समय पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे महिला क्रिकेट के इस ऐतिहासिक मुकाबले की अहमियत कम हो गई।

ऐतिहासिक मैच से हट गया सबका ध्यान - एलेक्स हार्टले ने कहा कि लॉर्ड्स में खेला जा रहा यह मुकाबला महिला क्रिकेट के इतिहास का

बेहद खास पल है। ऐसे समय में मैकुलम की विदाई का ऐलान करना समझदारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि ईसीबी चाहती तो इस घोषणा को टेस्ट खत्म होने तक टाल सकती थी। उनके मुताबिक इससे क्रिकेट जगत और प्रशंसकों का पूरा ध्यान महिला टेस्ट से हट गया।

ईसीबी की मंशा पर भी उठाए सवाल - हार्टले ने बोर्ड की महिला क्रिकेट के प्रति प्रतिबद्धता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर ईसीबी वास्तव में महिला क्रिकेट का सम्मान और विकास चाहता है तो उसे केवल बयान देने के बजाय अपने फैसलों से भी यह दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा, इस फैसले का कोई मतलब नहीं बनता। मंगलवार तक इंतजार किया जा सकता था। इंग्लैंड भले ही यह टेस्ट जीतने की स्थिति में नहीं है, लेकिन मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक मुकाबला है।

सिर्फ बातें नहीं, काम से दिखाइए सम्मान - हार्टले ने माना कि मंगलवार से इंग्लैंड पुरुष टीम को भारत के खिलाफ वनडे सीरीज खेलनी है, इसलिए ईसीबी घोषणा जल्द करना चाहता था। लेकिन उनके मुताबिक महिला क्रिकेट के लिहाज से यह टेस्ट उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा, अगर आप कहते हैं कि महिला क्रिकेट का सम्मान करते हैं और उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो सिर्फ बातें मत कीजिए। इस खबर को सोमवार शाम या मंगलवार सुबह तक रोका जा सकता था।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

क्या प्याज बालों का झड़ना रोक सकता है? जानिए इसका इस्तेमाल करने का सही तरीका

बाल झड़ने की समस्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है. आपको बता दें कि बाल झड़ने के लिए कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं. इन कारणों में हार्मोनल असंतुलन, तनाव, प्रदूषण, अनहेल्दी डाइट और बालों पर केमिकल वाले उत्पादों का इस्तेमाल शामिल हैं. बालों को झड़ने से रोकने के लिए लोग कई तरह के उपचार करवाते हैं, जिनके विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं. इसलिए बालों को झड़ने से रोकने के लिए घरेलू उपाय ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं. इन घरेलू उपायों में प्याज का तेल भी शामिल है. इसे घर पर बनाना भी आसान है...

प्याज का तेल बालों के लिए फायदेमंद है।

प्याज का तेल एक ऐसा तेल है जो बालों को झड़ने से रोकता है. प्याज से बना तेल बालों के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है और बालों को झड़ने से रोकता है.

प्याज का तेल बनाने के लिए सामग्री

3 प्याज

1/2 कप नारियल तेल

प्याज का तेल कैसे तैयार करें?

एक बर्तन में नारियल का तेल डालकर गैस पर रखें, फिर इसमें कटे हुए प्याज के टुकड़े डालकर तेल को 20 मिनट तक उबालें. इसके बाद गैस बंद कर दें. जब तेल अच्छे से ठंडा हो जाए तो इसे कांच के जार में डालकर इस्तेमाल करें.

का उपयोग कैसे करें?

तैयार तेल को स्कैल्प से लेकर बालों के सिरे तक अच्छी तरह से लगाएं. इसे अपने सिर पर 1 घंटे या रात भर के लिए लगा रहने दें और फिर नहा लें. हफ्ते में दो बार इसका इस्तेमाल करने से बालों का झड़ना कम होगा और रूसी जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा.

प्याज के तेल के उपयोग के लाभ

प्याज सल्फर का एक अच्छा स्रोत है. यह केराटिन के उत्पादन को बढ़ाता है, जो बालों के विकास के लिए जरूरी प्रोटीन है.

प्याज में एंटीबैक्टीरियल गुण भरपूर मात्रा में होते हैं. यह स्कैल्प पर होने वाले हर तरह के संक्रमण को रोकता है.

प्याज का तेल रूसी को रोकने और रूसी की समस्या से राहत दिलाने में मदद करता है.

प्याज का तेल रक्त परिसंचरण में सुधार करता है और बालों के विकास को बढ़ावा देता है.

प्याज के तेल का नियमित उपयोग बालों की जड़ों को मजबूत करता है और बालों का झड़ना रोकता है.

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ पर प्रकाशित परिणाम क्या कहते हैं कि एलियम सेपा, जिसे आम तौर पर प्याज के रूप में जाना जाता है, लिलियासी परिवार से संबंधित है. प्राचीन काल से, इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न रोगों के उपचार के लिए किया जाता रहा है. प्याज के अर्क में लिवर हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट और एचएमजी कोएंजाइम-ए रिडक्टेस की गतिविधियों को सामान्य करके हाइपोग्लाइसेमिक और हाइपोलिपिडेमिक प्रभाव भी पाए गए हैं. शोध के अनुसार, प्याज का अर्क पीने से ब्लड शुगर को तेजी से नियंत्रित करने में मदद मिलती है. इसके साथ ही प्याज में सल्फर भरपूर मात्रा में होता है, जो एक महत्वपूर्ण खनिज है जो बालों के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. सल्फर अमीनो एसिड में पाया जाता है, जो केराटिन सहित प्रोटीन के निर्माण खंड हैं. केराटिन बालों का एक प्रमुख घटक है, और हाई सल्फर सामग्री बालों की मजबूती और लोच को बढ़ाती है.

किचन में भूलकर भी न रखें ये 2 बर्तन उल्टे, घर से भाग जाएगी सुख-समृद्धि

हिंदू धर्म में वास्तु का विशेष महत्व है. घर के किचन के लिए भी वास्तु अनिवार्य है. किचन सिर्फ खाना बनाने के लिए ही नहीं होता, बल्कि इसमें अन्नपूर्णा का वास भी होता है. इसमें लक्ष्मी का भी वास होता है. इसलिए अगर आप घर में सुख-शांति और समृद्धि चाहते हैं तो किचन से जुड़े वास्तु नियमों का पालन जरूर करें. इनकी अनदेखी करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं. नतीजतन घर को नकारात्मक प्रभावों का भी सामना करना पड़ सकता है, ऐसा वास्तु ज्योतिष विशेषज्ञों का कहना है.

आमतौर पर लोग किचन में बर्तन धोने के बाद उन्हें उल्टा करके रख देते हैं. लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार किचन में कभी भी दो बर्तन को उल्टे नहीं रखने चाहिए, इसमें कड़ाही और तवा शामिल है. जी हां! वास्तु शास्त्र कहता है कि किचन में कभी भी कड़ाही और तवे को उल्टा नहीं रखना चाहिए. ऐसा करने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है.

जानकारों का कहना है कि ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिसका स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, खाना बनाने के बाद किचन में बर्तनों को धोना और उन्हें सही तरीके से रखना बहुत जरूरी है. नियमों का पालन करने से परिवार के सदस्यों के घर में समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है.

वास्तु शास्त्र कहता है कि तवा उल्टा रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और अक्सर घर में झगड़े होते रहते हैं. इसके साथ ही कहा जाता है कि घर में दरिद्रता बढ़ती है. इससे आर्थिक स्थिति भी खराब होने लगती है. कहा जाता है कि तवा उल्टा रखने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं. इससे घर की खुशियां खत्म हो जाती हैं. पैसों की कमी का सामना करना पड़ता है. इसलिए सलाह दी जाती है कि किसी भी हालत में तवा उल्टा नहीं रखना चाहिए. जब ??भी तवा धोएं तो उसे सीधा ही रखें. इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि गंदे बर्तन रातभर किचन में नहीं रखने चाहिए.

हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में सदैव खुशियां, सेहत और पैसे की कमी ना रहे. लेकिन कई बार हम भूल से कई छोटी-छोटी गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से घर में खुशियां और धन-दौलत लंबे वक्त तक नहीं टिक पाती. वास्तु शास्त्र के अनुसार, पूरे घर में शांति और जीवंतता बनाए रखने के लिए किचन में साफ-सफाई बेहद जरूरी है. यह सिर्फ खाने की जगह नहीं है. यह वह स्थान है जहां मां गृहलक्ष्मी का वास होता है.

वास्तु शास्त्र कहता है कि हल्दी, नमक, पानी का बर्तन, चावल, चीनी और घी ऐसी चीजें हैं जो हमेशा किचन में मौजूद होनी चाहिए. अगर ये पूरी तरह खत्म हो जाएं तो उस घर में आर्थिक तंगी, हेल्थ रिलेटेड परेशानियां और पारिवारिक कलह की संभावना बढ़ जाती है. इसलिए किचन में कुछ चीजों को संभालकर रखना चाहिए ताकि ये कभी पूरी तरह खत्म न हों.

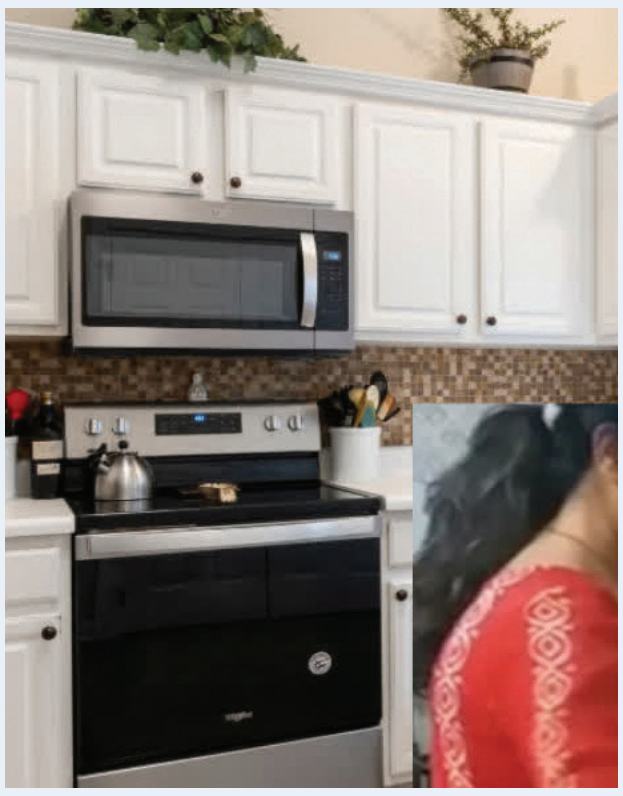

बरसात के मौसम में इन फलों का जरूर करें सेवन, बीमारियों से रहेंगे दूर और बढ़ेगी रोग प्रतिरोधक क्षमता

बारिश का मौसम शुरू हो गया है. हालांकि इस दौरान मौसम सुहावना होता है, लेकिन यह मौसम अपने साथ कई स्वास्थ्य समस्याएं भी लेकर आता है. मानसून के दौरान वायरल इंफेक्शन, एलर्जी, डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी कई मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. हवा में नमी भी काफी होती है, जिसका असर पाचन क्रिया पर पड़ता है.

मानसून के दौरान इंफेक्शन की संभावना बढ़ जाती है. चाहे कितनी भी सावधानी बरती जाए, संक्रामक रोग फिर भी हो ही जाते हैं. सर्दी-खांसी से लेकर डेंगू बुखार, मलेरिया, टाइफाइड और मच्छरों से होने वाली अन्य स्वास्थ्य समस्याएं मानसून के दौरान बढ़ जाती हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, कुछ फल खाने से मानसून के दौरान स्वास्थ्य समस्याओं से राहत मिल सकती है. इसके अलावा, कुछ फल संक्रमण से लड़ने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं.

मानसून के मौसम में अपनी सेहत का ध्यान रखना सबसे जरूरी है. ऐसे में पाचन और मौसमी बीमारियों से बचने के लिए आपको अपने खान-पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए. कहा जाता है कि मानसून के दौरान इम्यून सिस्टम का मजबूत होना सबसे जरूरी है. शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए कुछ फलों का सेवन जरूरी है. इन फलों को खाने से पाचन क्रिया बेहतर होती है. साथ ही इम्यून सिस्टम भी मजबूत बनता है.

इन फलों का जरूर करें सेवन

अमरूद : बरसात के दिनों में अमरूद खाना अच्छा होता है. अमरूद न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होता है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है अमरूद में विटामिन सी, आयरन और एंटी-ऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं. जो पाचन के लिए अच्छा होता है यह इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है.

अनार : अनार सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. इसे खाने से शरीर में खून की कमी दूर होती है. इसमें विटामिन बी और फोलेट भी भरपूर मात्रा में होता है. अगर आप मानसून में इस फल को अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो यह रेड ब्लड सेल्स की संख्या बढ़ाने में फायदेमंद होता है. लेकिन हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को अनार खाने से बचना चाहिए.

सेब : सेब विटामिन सी, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं. सेब के नियमित सेवन से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और एनर्जी भी मिलती है. मानसून में सेब खाने से वायरल इन्फेक्शन का खतरा कम होता है. सेब में फाइटोकेमिकल्स भी होते हैं, जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फायदेमंद होते हैं. इनमें पाया जाने वाला फाइबर कब्ज और वजन घटाने के लिए अच्छा माना जाता है. विशेषज्ञों का कहना है कि सेब के नियमित सेवन से उच्च रक्तचाप नियंत्रित रहता है, जिससे हृदय रोग का खतरा कम होता है.

पपीता : पपीता भी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है. मानसून में पपीता जरूर खाना चाहिए. पपीते में पपेन एंजाइम होता है. जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाने का काम करता है. साथ ही इसे खाने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है. साथ ही इसमें विटामिन ए और सी भरपूर मात्रा में होता है. साथ ही पपीते के पत्तों का जूस डेंगू बुखार में उपयोगी होता है. पपीते के पत्तों का जूस पीने से प्लेटलेट्स बढ़ती हैं. साथ ही यह सिरदर्द, थकान जैसी समस्याओं को भी दूर करता है.

नाशपाती : नाशपाती विटामिन सी से भरपूर होती है. यह इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने का काम करती है. मानसून में इसे खाना जरूरी है. यह पाचन के लिए भी जरूरी है. यह एक सुपरफूड है. कब्ज से परेशान लोग अगर नाशपाती खाएं तो इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं. क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है. जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए बहुत अच्छा होता है. इसके नियमित सेवन से मल को नरम करने में मदद मिलती है. नाशपाती कॉपर और फ्लेवोनॉयड जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है. जो शरीर में सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं. जर्नल मॉलिक्यूल्स में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, फ्लेवोनॉयड सूजन को कम करने और टाइप 2 और स्ट्रोक के रिस्क को कम करने में मदद कर सकते हैं.

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

बीएसएफ की सतर्कता से कठुआ में नाकाम हुई घुसपैठ की कोशिश

जम्मू (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों ने सतर्कता दिखाते हुए एक पाकिस्तानी घुसपैठिए की भारतीय सीमा में प्रवेश की कोशिश को नाकाम कर दिया। बीएसएफ की चेतावनी और चेतावनी स्वरूप की गई फायरिंग के बाद घुसपैठिया वापस पाकिस्तान की ओर भाग गया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। अधिकारियों के अनुसार, रविवार शाम कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर के बोबिया क्षेत्र में बीएसएफ के जवान नियमित निगरानी के दौरान सीमा पर संदिग्ध गतिविधि देख रहे थे। इसी दौरान एक व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर भारतीय क्षेत्र की ओर बढ़ने का प्रयास करते हुए देखा गया। जवानों ने तत्काल उसे रुकने की चेतावनी दी। बताया गया कि चेतावनी के बावजूद संदिग्ध व्यक्ति सीमा पर लगी सुरक्षा बाड़ की ओर लगातार बढ़ता रहा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बीएसएफ के जवानों ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए चेतावनी स्वरूप कुछ गोलियां चलाईं। फायरिंग की आवाज सुनते ही घुसपैठिया घबरा गया और तुरंत वापस पाकिस्तान की ओर भाग निकला। घटना के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई। बीएसएफ ने सीमा पर निगरानी बढ़ा दी है तथा आसपास के क्षेत्र में व्यापक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी अन्य घुसपैठ की कोशिश या संदिग्ध गतिविधि की संभावना न रहे। सुरक्षा एजेंसियां घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर चौबीसों घंटे कड़ी निगरानी रखी जा रही है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में समय-समय पर घुसपैठ की कोशिशें होती रही हैं, जिन्हें बीएसएफ और अन्य सुरक्षा बल अपनी सतर्कता और प्रभावी निगरानी के जरिए लगातार विफल करते रहे हैं। इस ताजा घटना ने एक बार फिर सीमा पर तैनात जवानों की मुस्तैदी और त्वरित प्रतिक्रिया को रेखांकित किया है।

कमजोर पड़ा मानसून, 372 जिले बारिश की कमी से प्रभावित ; खरीफ फसलों पर बढ़ा संकट

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश में मानसून की रफ्तार एक बार फिर धीमी पड़ गई है, जिससे कृषि क्षेत्र की चिंता बढ़ गई है। ताजा स्थिति के अनुसार देश के 372 जिले सामान्य से कम वर्षा की मार झेल रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर वर्षा की कमी बढ़कर 19 प्रतिशत तक पहुंच गई है। कमजोर बारिश का सबसे अधिक असर खरीफ फसलों की बुआई पर पड़ रहा है और किसानों की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्थिति को गंभीर मानते हुए 14 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक करने का फैसला किया है। बैठक में वर्षा की कमी वाले क्षेत्रों की स्थिति, फसलों पर पड़ रहे प्रभाव और किसानों को राहत देने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। साथ ही राज्यों को वैकल्पिक फसलें अपनाने और कृषि सलाह को गांव-गांव तक पहुंचाने के निर्देश दिए जा सकते हैं। बारिश में कमी के कारण धान, सोयाबीन, कपास, मक्का और अन्य खरीफ फसलों की बुआई पिछले वर्ष की तुलना में पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय लगातार राज्यों से जानकारी जुटा रहा है और हालात पर नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है, लेकिन इससे पूरे देश में वर्षा की कमी की भरपाई होने की उम्मीद कम है। सरकार का कहना है कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। वर्षा की स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर प्रभावित राज्यों को अतिरिक्त सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि कमजोर मानसून का असर खेती और खाद्य उत्पादन पर न्यूनतम रहे।

सुप्रीम कोर्ट में छलका सहारा निवेशक का दर्द, महिला बोली- पति की मौत हो गई, अब तो हमारी जमा पूंजी दिला दीजिए

नई दिल्ली (एजेंसी)। सहारा समूह में वर्षों पहले निवेश करने वाले लाखों लोगों की उम्मीदें एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में लगी रहीं। सुनवाई के दौरान एक महिला निवेशक भावुक हो गई और अदालत से हाथ जोड़कर अपनी जमा पूंजी वापस दिलाने की गुहार लगाई। महिला ने कहा कि उसके पति का निधन हो चुका है और परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहा है। उसने अदालत से कहा कि जीवनभर की बचत सहारा में फंसी हुई है, अब न्याय दिलाया जाए। महिला की भावुक अपील सुनकर अदालत ने उसकी बात सुनी और कहा कि ऐसे मामलों में निवेशकों की परेशानी को समझा जा रहा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सहारा से जुड़े मामलों और निवेशकों के भुगतान की प्रक्रिया पर पहले से सुनवाई चल रही है तथा इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सहारा प्रकरण लंबे समय से न्यायिक प्रक्रिया में है। वर्ष 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की दो कंपनियों को निवेशकों का पैसा लौटाने का आदेश दिया था। इसके बाद भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास जमा राशि से पात्र निवेशकों को भुगतान की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन बड़ी संख्या में निवेशक अब भी अपनी रकम मिलने का इंतजार कर रहे हैं। मौजूदा सुनवाई के दौरान अदालत के सामने निवेशकों की परेशानियां फिर प्रमुखता से सामने आईं। अदालत ने संकेत दिया कि लंबित मामलों के साथ निवेशकों के हितों पर भी विचार किया जाएगा। सहारा में निवेश करने वाले लाखों लोगों की नजर अब अदालत के अगले आदेश पर टिकी है, जिससे वर्षों से फंसी उनकी मेहनत की कमाई वापस मिलने की उम्मीद बनी हुई है।

फडणवीस बने महाराष्ट्र के तीसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले सीएम, शरद पवार का रिकॉर्ड टूटा

मुंबई (एजेंसी)।(महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के राजनीतिक इतिहास में एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है। वे तीन कार्यकालों को मिलाकर अब राज्य में तीसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले नेता बने हैं। इस मामले में उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के संस्थापक शरद पवार के कुल कार्यकाल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। जनवरी 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, सीएम फडणवीस कुल 2,430 दिनों (लगभग छह साल और सात महीने) तक मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, जबकि पवार ने चार अलग-अलग कार्यकालों में कुल 2,412 दिनों तक राज्य की कमान संभाली थी।

मोदी कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें तेज: शाह-यादव से जुड़ी घटनाओं से हलचल

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कैबिनेट विस्तार या बड़े राजनीतिक फैसलों का अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि उनकी रणनीतिक योजनाएं अत्यंत गोपनीय रहती हैं। हालांकि, हाल की दो घटनाओं ने मानसून सत्र से पहले संभावित कैबिनेट फेरबदल की अटकलों को हवा दी है।

पहली घटना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इंटेलिजेंस ब्यूरो के निवर्तमान डायरेक्टर तपन डेका के सम्मान में आयोजित डिनर है। एक दुर्लभ सार्वजनिक कदम उठाकर केंद्रीय मंत्री शाह ने एक्स पर डेका की प्रशंसा करते हुए कार्यक्रम की तस्वीरें साझा कीं। इससे अटकलें हैं कि डेका को सेवानिवृत्ति के बाद जम्मू-कश्मीर से जुड़ी कोई अहम जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की संभावना बढ़ती है।

दूसरी अहम घटना केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में अचानक हुए प्रशासनिक फेरबदल से जुड़ी है, जिसमें उनके चार अहम निजी सहयोगियों को हटाया गया। केंद्रीय मंत्री यादव को बीजेपी के प्रमुख रणनीतिकार और संगठन से जुड़े अहम व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, जिनका प्रभाव उनकी मंत्री पद की जिम्मेदारियों से कहीं अधिक है। इस अप्रत्याशित कदम ने राजनीतिक और नौकरशाही हलकों में हलचल मचा दी है। विपक्षी कांग्रेस ने, पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश के नेतृत्व में, सरकार पर कुशासन और यादव के मंत्रालय में बड़े घोटाले का आरोप लगाया है। यह घटना किसी बड़े बदलाव का संकेत है या मात्र एक प्रशासनिक कदम, यह देखना बाकी है, लेकिन इससे यादव को लेकर अटकलें तेज कर दी हैं।

हालांकि, सूत्रों का कहना है कि संसद के मॉनसून सत्र (20 जुलाई से पहले) में कैबिनेट में फेरबदल की संभावना कम है। सरकार का मुख्य ध्यान विधायी कार्यों पर है और प्रधानमंत्री का शेड्यूल भी बहुत व्यस्त है। 20 जुलाई से पहले विस्तार होने पर नए मंत्रियों के पास सत्र की तैयारी के लिए कम समय होगा। इसके बावजूद, सत्र से ठीक पहले भी फेरबदल के उदाहरण रहे हैं, जैसे जुलाई 2021 में कई वरिष्ठ मंत्रियों को हटाकर नए चेहरों को शामिल किया गया था।

डीएम कार्यालय को मिली बम से उड़ाने की धमकी, परिसर में सघन तलाशी अभियान जारी

नई दिल्ली (एजेंसी)। उत्तरप्रदेश के ग्रेटर नोएडा से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) कार्यालय को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस धमकी भरे संदेश के मिलते ही प्रशासनिक महकमे और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। स्थानीय पुलिस तुरंत एक्शन मोड में आई और अधिकारियों व आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को छावनी में बदल दिया गया। सुरक्षा के तय मानकों के तहत आनन-फानन में बम डिस्पोजल स्क्वाड (बीडीएस), डॉग स्क्वाड, फायर ब्रिगेड और एंटी-सबोटेज टीमों को मौके पर बुलाया गया। इन संयुक्त सुरक्षा एजेंसियों ने डीएम कार्यालय की गहन तलाशी ली। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, अब तक की जांच में परिसर के भीतर कोई भी संदिग्ध या आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है, जिससे प्रशासन ने राहत की सांस ली है। हालांकि, एहतियात के तौर पर पूरे कार्यालय और उसके आस-पास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। दूसरी ओर, पुलिस की साइबर सेल ने धमकी भरे ईमेल की तकनीकी जांच शुरू कर दी है। डिजिटल सबूतों और आईपी एड्रेस को खंगाला जा रहा है, ताकि पता लगा सके कि यह ईमेल कहां से भेजा गया था और इसके पीछे किसका हाथ है। गौरतलब है कि हाल ही में दिल्ली पुलिस ने गाजियाबाद से एक मानसिक रूप से बीमार युवक को गिरफ्तार किया था, जिसने इसरो और एनआईए जैसे प्रमुख संस्थानों को ऐसी ही झूठी धमकियां भेजी थीं। फिलहाल, पुलिस इस मामले को भी गंभीरता से लेकर हर पहलू की बारीकी से तफ्तीश कर रही है।

बद्रीनाथ दान चोरी: एसआईटी ने प्रमोद नौटियाल को किया गिरफ्तार

देहरादून(एजेंसी)। उत्तराखंड के चमोली में स्थित विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे और दान की धनराशि में हुई गंभीर गड़बड़ी के मामले में आखिरकार बड़ी कार्रवाई की गई है। इस प्रकरण में जांच कर रही एसआईटी (विशेष जांच दल) ने आरोपी अधिकारी प्रमोद नौटियाल को गिरफ्तार कर लिया है। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, एसआईटी की टीम ने प्रमोद नौटियाल को बीते 12 जुलाई की रात लगभग 8ः00 बजे देहरादून से हिरासत में लिया। गिरफ्तारी के बाद नौटियाल को पूछताछ और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए बद्रीनाथ लाया गया है। गौरतलब है कि बद्रीनाथ धाम में दान के पैसों में हेराफेरी का यह संवेदनशील मामला बीते 2 जुलाई को पहली बार प्रकाश में आया था, जिसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बेहद गंभीरता से लिया और तत्काल प्रभाव से जांच के आदेश दिए थे।

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, एसआईटी अब अन्य संदिग्धों की पहचान करने में जुटी है और आने वाले समय में इस प्रकरण में कई और लोगों पर भी शिकंजा कसने की संभावना जताई जा रही है। वहीं, इस पूरे विवाद की आंतरिक जांच कर रही बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) की एक चार सदस्यीय टीम भी आज अपनी जांच रिपोर्ट सौंप सकती है। इस टीम ने बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा और दान की धनराशि में हुई कथित गड़बड़ी की गहराई से पड़ताल की है। बीकेटीसी की यह विस्तृत रिपोर्ट सीसीटीवी फुटेज और संबंधित कर्मचारियों के लिखित बयानों सहित अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों पर आधारित होगी। यह प्रकरण विशेष रूप से बीते 2 जुलाई को चढ़ावा गणना के दौरान हुई हेरफेर से संबंधित बताया जा रहा है, जिसने मंदिर की पवित्रता और श्रद्धालुओं की आस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे। दरअसल, यह पूरा मामला तब सामने आया जब सोशल मीडिया पर एक कथित लेटर तेजी से वायरल हो गया। इस लेटर के सामने आते ही पूरे देवभूमि उत्तराखंड में बवाल मच गया और विपक्षी दलों ने राज्य सरकार को इस मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया था। वायरल हुए इस लेटर में बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के कर्मचारियों पर मंदिर के भीतर आने वाले दान और चढ़ावे की रकम में हेरफेर करने के बेहद गंभीर आरोप लगाए गए थे। करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े इस पावन धाम में कथित गड़बड़ी की खबर आग की तरह फैलते ही तीर्थ पुरोहितों, स्थानीय हक-हकूकधारियों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक में जबरदस्त उबाल आ गया था। श्रद्धालुओं के बीच भी यह खबर चिंता का विषय बन गई थी। एसआईटी द्वारा की गई यह पहली गिरफ्तारी इस बात का संकेत है कि जांच एजेंसियां इस मामले को गंभीरता से ले रही हैं और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अब सबकी निगाहें बीकेटीसी की रिपोर्ट और एसआईटी की आगे की कार्रवाई पर टिकी हैं, यह देखना होगा कि इस बड़े घोटाले में और कितने नाम सामने आते हैं और न्याय कब तक मिल पाता है।

ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा का नारा साबित हुआ खोखला

-भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर किया हमला

नई दिल्ली(एजेंसी)। कांग्रेस ने देश में उजागर हो रहे विभिन्न भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा, कि प्रधानमंत्री का वर्ष 2014 में दिया गया ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा का नारा वास्तविकता में खोखला साबित हुआ है। उन्होंने दावा किया कि सरकार के कार्यकाल में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनसे भ्रष्टाचार विरोधी दावों पर सवाल खड़े होते हैं।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट जारी करते हुए कहा, कि मई 2014 में सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया था, लेकिन समय के साथ यह दावा खोखला साबित हुआ। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि मौजूदा स्थिति खाऊंगा, खाने दूंगा और खिलाऊंगा जैसी बन गई है।

कांग्रेस नेता ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नोटबंदी पर दिए गए उस बयान का भी उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने इसे संगठित लूट और कानूनी रूप से वैध ठहराई गई लूट बताया था। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (जीएसपीसी) का ओएनजीसी में विलय कर कथित वित्तीय अनियमितताओं को दबाने का प्रयास किया गया। उन्होंने चुनावी बॉन्ड योजना को भी निशाने पर लेते हुए इसे चंदा दो, धंधा लो व्यवस्था करार दिया और आरोप लगाया कि इससे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला।

जारी विभिन्न रिपोर्टों का दिया हवाला

कांग्रेस ने अदाणी समूह, राफेल सौदे, पीएम केयर्स फंड तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की विभिन्न रिपोर्टों का हवाला देते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। जयराम रमेश ने दावा किया कि हाल के सप्ताहों में सामने आए कई मामलों ने सरकार की पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाए हैं। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे के कथित दुरुपयोग, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर रिश्तेदारों को कथित लाभ पहुंचाने के आरोप, विपक्षी दलों के नेताओं को वित्तीय प्रलोभन देकर दल बदल कराने, एक केंद्रीय राज्य मंत्री द्वारा सरकारी योजना की सब्सिडी लेने तथा पर्यावरण मंत्रालय में अधिकारियों के तबादलों जैसे मुद्दों का भी उल्लेख किया।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री पर साधा निशाना

जयराम रमेश ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल में परीक्षा प्रणाली भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से प्रभावित हुई है, जिससे करोड़ों छात्रों के भविष्य पर प्रतिकूल असर पड़ा है। कांग्रेस ने इन सभी मामलों की निष्पक्ष जांच कराने तथा केंद्र सरकार से जवाब देने की मांग की है।

कोलकाता एयरपोर्ट मस्जिद विवाद: शुभेंदु अधिकारी का बयान, राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे ऊपर

कोलकाता (एजेंसी)। कोलकाता एयरपोर्ट के भीतर स्थित पुरानी मस्जिद में सामूहिक नमाज़ पर रोक लगाने और उसके प्रस्तावित स्थानांतरण को लेकर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक घमासान तेज हुआ है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि बताकर अपना रुख साफकिया है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने धार्मिक स्वतंत्रता का बचाव किया है। सीएम अधिकारी ने विवाद पर टिप्पणी कर कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि चीन और बांग्लादेश जैसे संवेदनशील पड़ोसी देशों के करीब स्थित भू-रणनीतिक महत्व के इंस्टॉलेशन (एयरपोर्ट) के गेट बाहरी लोगों के लिए खुले नहीं रखे जा सकते। सीएम अधिकारी ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा और एयरपोर्ट की सुरक्षा को अन्य सभी चीजों से ज़्यादा प्राथमिकता मिलेगी। वहीं, सीएम सुवेंदु ने विपक्ष के उन आरोपों को खारिज किया कि उनकी सरकार धार्मिक रीति-रिवाजों में बाधा डालती है। उन्होंने कहा, हमने किसी को भी अपने धर्म का पालन करने से नहीं रोका है, जैसा कि विपक्ष ने हमारे बारे में कहा था। मुख्यमंत्री सुवेंदु ने उदाहरण देकर बताया कि बकरीद (ईद-उल-अज़्हा) जानवरों की बलि से जुड़े कानूनों का पालन कर मनाई गई और मुहर्रम बिना हथियार लहराए शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, जिससे कोई समस्या नहीं हुई। मुख्यमंत्री सुवेंदु ने नागरिकों से कानून का पालन करने और धर्म को एक निजी मामले के रूप में देखने का आग्रह किया, ताकि सब कुछ ठीक-ठाक चलता रहे।

इस बीच, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने मस्जिद को स्थानांतरित करने के प्रस्ताव का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट के विस्तार और सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए कदम ज़रूरी है। मजूमदार ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने तुष्टिकरण की राजनीति के कारण इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं की थी, जबकि उनकी मौजूदा सरकार ऐसी राजनीति में विश्वास नहीं रखती और मस्जिद को दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाएगा।

दूसरी ओर, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद सौगत रॉय ने बांकरा मस्जिद में प्रवेश पर अनिश्चितकालीन रोक और उसके स्थानांतरण के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। ममता के नेता रॉय ने कहा कि मुस्लिम समुदाय की सहमति के बिना मस्जिद के संबंध में कोई भी निर्णय नहीं होना चाहिए।

यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब राज्य सरकार ने शनिवार को सुरक्षा कारणों का हवाला देकर बांकरा मस्जिद (जिसे गौरीपुर जामा मस्जिद भी कहा जाता है) को दूसरी जगह स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर मौजूद मस्जिद में मरम्मत कार्य के चलते तीन दिनों के लिए नमाज़ रोक दी गई है। माना जाता है कि 130 साल से भी ज़्यादा पुरानी यह मस्जिद एयरपोर्ट के निर्माण से भी पहले से मौजूद है और यह एयरपोर्ट के सेकेंडरी रनवे से करीब 165 मीटर की दूरी पर स्थित है।

पीएम मोदी की पंजाब यात्रा से पहले खालिस्तानी हुए सक्रिए

भोपाल (एजेंसी)। नई दिल्ली,(ईएमएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा से पहले राज्य में खालिस्तान समर्थक तत्वों की सक्रियता चिंता का विषय बन गई है। संभावना है कि प्रधानमंत्री 15 और 17 जुलाई के बीच पंजाब का दौरा कर सकते हैं, जिसमें लुधियाना और जालंधर में कार्यक्रम और चंडीगढ़ में कई विकास कार्यों का उद्घाटन शामिल है। हाल ही में एक वीडियो सामने आया है जिसमें दिल्ली जा रही एक ट्रेन पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। यह ट्रेन फिरोजपुर कैंट रेलवे स्टेशन पर थी और इस वीडियो को अलगाववादी समूह सिख्स फॉर जस्टिस (एसएफजे) के संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू ने पोस्ट किया था। हालांकि, इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं की जा सकती है, लेकिन घटना के बाद पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गए हैं।

पन्नू ने अपने वीडियो में मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा का नाम भी लिया है, जो अपनी फिल्म सतलुज के कारण इन दिनों फिर से चर्चा में हैं। पन्नू ने पीएम मोदी की आगामी यात्रा के दौरान खालिस्तानी झंडे दिखाने का आह्वान किया है।

रिपोर्ट के अनुसार, पन्नू ने दावा किया है कि खालड़ा ने 90 के दशक में अज्ञात शवों से जुड़े मामलों के दस्तावेज तैयार किए थे, जो मानवाधिकार उल्लंघन के एक पैटर्न को दर्शाते हैं। इस बीच, अधिकारियों ने फिरोजपुर कैंट रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है ताकि ट्रेन पर नारे लिखने वाले व्यक्तियों की पहचान की जा सके। पुलिस मौका-ए-वारदात से फॉरेंसिक सबूत भी जुटा रही है और पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी कर दी गई है। दूसरी ओर, दिलजीत दोसांझ अभिनीत फिल्म सतलुज भी विवादों के केंद्र में है। इस फिल्म का शीर्षक पहले पंजाब 95 था। यह फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने 1984 और 1994 के बीच पंजाब में हजारों अज्ञात शवों के गैर-कानूनी ढंग से किए गए अंतिम संस्कार की जांच की थी। इसे 3 जुलाई को रिलीज होने के दो दिन बाद ही ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 से हटा दिया गया था, क्योंकि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सुरक्षा संबंधी चिंताएं व्यक्त की थीं। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने फिल्म निर्माताओं पर विवादित दावों को स्थापित इतिहास के तौर पर पेश करने का आरोप लगाया है। बिट्टू, जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं, ने कहा कि पंजाब का दर्दनाक अतीत कोई ऐसी पटकथा नहीं है जिसे किसी विमर्श के हिसाब से चुनिंदा ढंग से संपादित किया जा सके। उन्होंने फिल्म निर्माताओं को 25,000 लोगों के लापता होने या उन्हें गैर-कानूनी तरीके से अंतिम संस्कार किए जाने के सभी दस्तावेजी सबूत, सरकारी रिकॉर्ड और न्यायिक निष्कर्ष सार्वजनिक करने की चुनौती दी है, जैसा कि फिल्म में दर्शाया गया है। यह विवाद और खालिस्तानी तत्वों की सक्रियता प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे से पहले राज्य में सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर रही है।

राजभर का अखिलेश पर तीखा हमला, सपा शासन गुंडागर्दी और जातीय हिंसा का दौर

- कहा- सपा राज में अपराधियों का मनोबल बढ़ा था ; और घटनाओं को भी जनता के सामने लाएंगे

लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके पूर्ववर्ती शासन पर तीखा हमला बोला है। राजभर ने अखिलेश यादव के कार्यकाल को गुंडागर्दी, अराजकता और जातीय हिंसा का खौफनाक दौर करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखे अपने पोस्ट में सपा शासनकाल की दो चर्चित जघन्य घटनाओं - बुलंदशहर सामूहिक दुष्कर्म और बदायूं में दलित बहनों के बलात्कार एवं हत्या - का विशेष रूप से जिक्र किया। राजभर ने आरोप लगाया कि सपा राज में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ था और उन्होंने ऐसी अन्य घटनाओं को भी जनता के सामने लाने की बात कही। राजभर ने अपने बयान की शुरुआत एक हालिया घटना का जिक्र करते हुए कहा ?कि अखिलेश यादव दो दिन पहले आपके लोगों की गुंडई देखकर मुझे आपके कार्यकाल की सपाई गुंडागर्दी, अराजकता और आतंक का खौफनाक दौर याद दिला दिया। उन्होंने कहा कि सपा सरकार के कर्म और कांड आज भी उनकी आंखों के सामने तैरने लगते हैं। मंत्री राजभर ने 2016 की बुलंदशहर सामूहिक दुष्कर्म घटना का उल्लेख किया, जिसमें दिल्ली-कोलकाता नेशनल हाईवे पर एक मां और उसकी नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप हुआ था। उन्होंने मां की मार्मिक गुहार का भी जिक्र किया और तत्कालीन रामपुर के सपा नेता आजम खान के उस घटना पर दिए गए अशोभनीय बयान की भी याद दिलाई। राजभर ने दावा किया कि योगी सरकार में इस मामले के मुख्य आरोपी को 2020 में गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, और पुलिस पर हमला करने के प्रयास के बाद उसे ठोक दिया गया। अपने पोस्ट में राजभर ने 2014 के बदायूं कांड का भी हवाला दिया, जहां दो दलित बहनों के साथ बलात्कार के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी और लाशों को पेड़ पर लटका दिया गया था। उन्होंने

आरोप लगाया कि इस मामले के ज्यादातर आरोपी अखिलेश यादव के स्वजातीय थे और आर्टिकल 15 जैसी फिल्म बनाकर इस मामले को सामान्य करने की कोशिश की गई। मंत्री राजभर ने अखिलेश यादव को तैयार रहने को कहते हुए कहा कि वह सपा सरकार की एक जनपद-एक जातीय हिंसा की पूरी फेहरिस्त जनता के सामने खोलेंगे। उन्होंने अति पिछड़ों और दलितों पर हुए अत्याचारों, मारपीट, हत्या और बलात्कार की घटनाओं को याद दिलाते हुए कहा कि लोग इन जुल्मों को भूले नहीं हैं।

मैसेजिंग ऐप्स के लिए समान नियम बनाने की तैयारी में केंद्र

-प्रस्तावित फीचर्स पर बनेगा साझा ढांचा, सभी प्लेटफॉर्म से विचार-विमर्श के बाद होगा अंतिम फैसला

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार देश में संचालित सभी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के लिए समान नियामकीय मानक (कॉमन स्टैंडर्ड्स) तैयार करने पर विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एक ऐसे ढांचे को तैयार करने पर काम कर रहा है, जिससे विभिन्न मैसेजिंग सेवाओं पर एक जैसे नियम लागू किए जा सकें और नए फीचर्स को लेकर लिए जाने वाले सरकारी निर्णयों को स्पष्ट कानूनी आधार मिल सके।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार को व्हाट्सऐप के प्रस्तावित यूजरनेम फीचर को लेकर कुछ सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं। अधिकारियों का मानना है कि यदि उपयोगकर्ताओं की पहचान केवल यूजरनेम के आधार पर होने लगे तो किसी अन्य व्यक्ति का रूप धारण करने (इम्पर्सोनेशन), ऑनलाइन धोखाधड़ी, तथाकथित डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों और जांच एजेंसियों के सामने आने वाली चुनौतियों का जोखिम बढ़ सकता है। हालांकि, इस संबंध में सरकार की ओर से अभी कोई अंतिम निर्णय घोषित नहीं किया गया है। रिपोर्टों के अनुसार, मंत्रालय इस मुद्दे पर सभी प्रमुख मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के साथ चर्चा करने की तैयारी कर रहा है।

सरकार का उद्देश्य ऐसा समान नियामकीय ढांचा तैयार करना है, जिसमें किसी एक मंच पर किसी फीचर को प्रतिबंधित करने और दूसरे मंच पर उसी सुविधा की अनुमति देने जैसी स्थिति से बचा जा सके। अधिकारियों का मानना है कि वर्तमान व्यवस्था में ऐसे मामलों के लिए स्पष्ट और समान नियमों का अभाव है। इसलिए भविष्य में किसी भी नए फीचर के मूल्यांकन और अनुमति से संबंधित निर्णय एक समान मानकों के आधार पर लिए जा सकें, इसके लिए साझा दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे हैं।

सरकार का कहना है कि अंतिम निर्णय लेने से पहले सभी संबंधित मैसेजिंग प्लेटफॉर्म और अन्य हितधारकों से व्यापक विचार-विमर्श किया जाएगा। विचार-विमर्श के बाद सभी पहलुओं को सामने रख कर उचित फैसला लिया जा सकेगा। इसके बाद ही किसी नए नियामकीय ढांचे या दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया जाएगा। फिलहाल इस संबंध में कोई औपचारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त समाचार

फिनलैंड में हैदराबाद के छात्र का शव मिला, 2 महीने से लापता था ; पुलिस बोली– हत्या के सबूत नहीं

हेलसिंकी, एजेंसी। फिनलैंड में पिछले दो महीने से लापता हैदराबाद के 18 साल के छात्र का शव समुद्र से बरामद हुआ है। फिनलैंड पुलिस ने कहा है कि शुरुआती जांच में हत्या के सबूत नहीं मिले हैं। परिवार ने भारत सरकार से उनका शव जल्द भारत लाने में मदद की अपील की है, ताकि अंतिम संस्कार किया जा सके। छात्र की पहचान मणिदीप रुप में हुई है, जो 2025 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए फिनलैंड गया था। 5 मई को वह ट्रेन से राजधानी हेलसिंकी पहुंचा और आखिरी बार एक मार्केट स्टोर में नजर आया। परिवार के मुताबिक, 5 मई को मणिदीप ने मां से आखिरी बार बात की थी। उसने बताया था कि वह एक बेकरी में हैं और जल्द घर लौटेगा। इसके बाद उसका फोन बंद हो गया और कोई संपर्क नहीं हो सका। मामले के बाद फिनलैंड की जांच एजेंसियों, हेलसिंकी पुलिस और कोस्ट गार्ड ने कई हफ्तों तक तलाशी अभियान चलाया। आखिरकार 9 जुलाई को समुद्र से उनका शव बरामद हुआ।

अमेरिका में भारतीय मूल की महिला की हत्या : बेटा घायल, आरोपी पति गिरफ्तार

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में एक व्यक्ति को अपनी भारतीय मूल की पत्नी की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या करने और अपने बेटे को घायल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। आरोपी किर्क बी रेजियन (56 वर्षीय) को मंगलवार रात अटलांटा के पास कॉब काउंटी में घटनास्थल से गिरफ्तार किया गया। स्थानीय मीडिया के अनुसार, उसे कॉब काउंटी के वयस्क हिरासत केंद्र में रखा गया है और जमानत पर रिहा नहीं किया गया है। उनकी पत्नी 57 वर्षीय शीतल रेजियन स्मिरना में लॉरेल क्रीक ट्रेल स्थित अपने घर के अंदर घायल मिलीं। उन्हें गोली लगी हुई थी। बाद में उनकी मौत हो गई। उनके 23 वर्षीय बेटे जेसन रेजियन घर के बाहर गोली लगने से घायल हालत में मिले। आपातकालीन टीम उन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले गई। पुलिस को रात करीब 8 बजे सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति को गोली लगी है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। जांच में पुलिस ने किर्क रेजियन की पहचान शीतल के पति और जेसन के पिता के रूप में की। स्थानीय समाचारों के अनुसार, कॉब काउंटी पुलिस ने किर्क पर हत्या, गंभीर हमले के दो आरोप और किसी गंभीर अपराध के दौरान हथियार रखने के दो आरोप लगाए हैं। पुलिस ने इस घटना को घरेलू हिंसा का मामला बताया। पुलिस के अनुसार, आम लोगों के लिए अब कोई खतरा नहीं है। अधिकारियों ने अभी तक यह नहीं बताया है कि गोलीबारी किस वजह से हुई। जेसन की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में भी कोई नई जानकारी नहीं दी गई है। जांच के दौरान पुलिस ने कई घंटों तक लॉरेल क्रीक ट्रेल इलाके को बंद रखा। इस घटना से इलाके के लोग हैरान हैं। यहां कुछ परिवार कई दशकों से रह रहे हैं।

इजरायली पीएम नेतन्याहू के बेटे ने टैक्स से बचने के लिए बदला नाम?

येरुशलम, एजेंसी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के परिवार से जुड़ा एक और नया विवाद सामने आया है। नेतन्याहू के बड़े बेटे यायर नेतन्याहू ने अपना नाम बदलकर योनातन हुन कर लिया है। लीक हुए डेटा के मुताबिक, नेतन्याहू के बेटे ने यह काम पिछले दो सालों के दौरान ही किया है। क्योंकि 2024 में टैक्स भरने के दौरान उन्होंने अपने जन्म वाले नाम का ही प्रयोग किया था। लेकिन 2026 में जब उन्होंने टैक्स फाइलिंग की, तो अपना नाम बदलकर 'योनातन हुन' कर लिया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू परिवार टैक्स और भ्रष्टाचार के मामलों में फंसा हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री के बड़े बेटे के इस कदम को भी शक की नजर से देखा जा रहा है। हालांकि, अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि 34 साल के एक्टिविस्ट और पीएम नेतन्याहू के बेटे ने किन वजहों से यह नाम बदला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपने नाम में यह बदलाव रेगुलेटरी अपडेट उनके मौजूदा नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर के तहत किया गया है। इसमें उन्होंने अपना रेसिडेंशियल एड्रेस बस 'बाल्फोर 0' के नाम से दिया है। यह एड्रेस इजरायल के प्रधानमंत्री आवास की तरफ इशारा करता है। पिछले कई सालों से युद्ध में उलझे इजरायल के लोगों के बीच में प्रधानमंत्री के बेटे द्वारा नाम बदलने को लेकर काफी चर्चा है। लोग इस फैसले के पीछे के मकसद को लेकर बंटे हुए हैं। क्योंकि एक तरफ जहां युद्ध के लिए सभी रिजर्व सैनिकों को बुलाया जा चुका है, वहीं 34 वर्षीय योनातन हुन 2023 से फ्लोरिडा में रह रहे हैं। विदेश में रहने की वजह से इजरायल में उनकी कड़ी आलोचना भी हुई थी। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने युद्ध में लड़ने से बचने के लिए यह तरकीब अपनाई है, वहीं कई लोग इसे टैक्स से जोड़कर देख रहे हैं। इजरायल के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार ने भले ही बेटे के नाम बदलने को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी हो, लेकिन लोगों ने इसका मतलब निकालना शुरू कर दिया है।

ईरान का विध्वंसक पलटवार ! कतर, यूएई और बहरीन पर दागीं मिसाइलें ; खाड़ी देशों में भारी तबाही

तेहरान, एजेंसी। पश्चिम एशिया में तनाव अब चरम पर पहुंच गया है और युद्ध की आग पूरे क्षेत्र में फैलती नजर आ रही है। रविवार सुबह ईरान ने अमेरिका के साथ जारी संघर्ष में एक बड़ा कदम उठाते हुए खाड़ी के प्रमुख देशों संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन और जॉर्डन पर भीषण मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। इन हमलों के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में हड़कंप मच गया है और कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिए हैं।

कतर और बहरीन में सायरन की गूंज : कतर की राजधानी दोहा में रविवार सुबह तेज धमाकों की आवाजें सुनी गईं, जिससे वहां रहने वाले लोग दहशत में आ गए। कतर के आंतरिक मंत्रालय ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पूरे देश के नागरिकों के मोबाइल फोन पर एक आपातकालीन सुरक्षा अलर्ट भेजा है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा खतरे का स्तर वर्तमान में बहुत अधिक है, इसलिए सभी नागरिक और प्रवासी अपने घरों या सुरक्षित स्थानों के भीतर ही रहें। वहीं, बहरीन के गृह मंत्रालय ने भी अपने क्षेत्रों में 'एयर रेड सायरन' चालू कर दिए हैं और लोगों से शांत रहते हुए नजदीकी सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है।

यूएई का एयर डिफेंस सिस्टम एक्शन में : ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलों को रोकने के लिए संयुक्त अरब अमीरात ने अपनी पूरी सैन्य ताकत झोंक दी है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक पुष्टि की है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने देश के विभिन्न हिस्सों में ईरान की ओर से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और आक्रामक ड्रोनों को हवा में ही इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया है। मंत्रालय ने बताया कि शहर में सुनी गई धमाकों की आवाजें वास्तव में ईरानी मिसाइलों को मार गिराने की कार्रवाई का परिणाम थीं।

'खून का बदला' : ईरान की यह कार्रवाई उसके सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के निधन और उनके जनाजे की रस्मों के तुरंत बाद शुरू हुई है। ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वे अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का 'खून का बदला' लेंगे। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (आईआरजीसी) ने भी पहले ही चेतावनी दी थी कि वे अपनी जमीन पर हुए किसी भी हमले का पूरी ताकत से जवाब देंगे।

होर्मुज विवाद के बाद बढ़ी टेंशन

ईरान का यह पलटवार दरअसल अमेरिका द्वारा ईरानी शहरों बुशहर, बंदर अब्बास, सिरिक और चाबहार पर की गई बमबारी के जवाब में है। तनाव का मुख्य केंद्र 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुजट' है, जिसे रविवार से आईआरजीसी ने बंद कर दिया है। आईआरजीसी ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य आगे की सूचना मिलने तक बंद रहेगा। यह स्थिति तब तक जारी रहेगी, जब तक पूरे क्षेत्र में अमेरिका का हस्तक्षेप खत्म नहीं हो जाता। अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी।

ईरान पर हवाई हमलों का नया दौर पूरा, करीब 140 ठिकानों को बनाया निशाना: अमेरिकी सेना : अमेरिकी सेना की मध्य कमान (सेंटकॉम) ने रविवार को कहा कि उसने ईरान पर हवाई हमलों का नया दौर पूरा कर लिया है। सेना के अनुसार, इन हमलों में करीब 140 ठिकानों को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम ने बताया कि निशाना बनाए गए ठिकानों में मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करने वाली जगहें, हथियार और गोला-बारूद रखने के ठिकाने, संचार उपकरण और अन्य स्थान शामिल थे। अमेरिकी सेना ने कहा कि इन हमलों से ईरान की उस क्षमता को कमजोर किया गया है, जिसके जरिये वह होर्मुज जलडमरूमध्य से स्वतंत्र रूप से गुजरने वाले आम नाविकों और व्यावसायिक जहाजों पर हमला कर सकता है। अमेरिकी सेना के अनुसार, ईरान ने रविवार सुबह इसके जवाब में बहरीन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर हमले किए।

हमले के बाद चालक दल ने जहाज छोड़ा: यूकेएमटीओ : यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (यूकेएमटीओ) ने बताया कि होर्मुज जलडमरूमध्य में हमले का निशाना बने मालवाहक जहाज के चालक दल ने जहाज छोड़ दिया है और लाइफबोट में सवार हो गया है। यूकेएमटीओ के अनुसार, यह जानकारी सैन्य अधिकारियों और जहाज की सुरक्षा टीम के अधिकारी से मिली है। इससे पहले अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) ने दावा किया था कि ईरान के इस्लामी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजर रहे साइप्रस के झंडे वाले मालवाहक जहाज एम/वी जीएफएस गैलेक्सी पर हमला किया। सेंटकॉम के मुताबिक, जहाज के चालक दल का एक सदस्य लापता है। जहाज में आग लगने और इंजन कक्ष को भारी नुकसान होने के कारण वह अपनी यात्रा जारी नहीं रख सका।

अरबों डॉलर का निवेश, फिर भी इंसानों की जगह नहीं ले सके रोबोट ; ह्यूमनॉइड रोबोट का कारोबार तेजी से बढ़ा

हांगकांग/बीजिंग , एजेंसी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और रोबोटिक्स के क्षेत्र में चीन ने ह्यूमनॉइड रोबोट के विकास में उल्लेखनीय बढ़त बनाई है। चीन की कंपनियां दुनिया में सबसे अधिक ह्यूमनॉइड रोबोट तैयार कर रही हैं और सरकार इस क्षेत्र में अरबों डॉलर का निवेश कर रही है। हालांकि, इन रोबोटों का तेजी से बढ़ता किराया कारोबार यह भी दिखा रहा है कि मौजूदा तकनीक अभी इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि कारखानों, दफ्तरों या घरों में बड़े पैमाने पर इन्सानों की जगह ले सके। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार चीन में पिछले एक वर्ष के दौरान ह्यूमनॉइड रोबोट किराये पर उपलब्ध कराने का कारोबार तेजी से बढ़ा है। प्रदर्शनी, व्यावसायिक आयोजनों, प्रचार अभियानों और विवाह प्रस्ताव जैसे विशेष कार्यक्रमों में लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इन रोबोटों की मांग बढ़ी है। एक रोबोट का दैनिक किराया लगभग 3,000 से 3,500 युआन तक है और कई मामलों में इसके साथ प्रशिक्षित ऑपरेटर भी उपलब्ध कराया जाता है। सरकारी मीडिया के अनुसार चीन में 1.53 लाख से अधिक रोबोट किराया कारोबार पंजीकृत हो चुके हैं। इन चुनौतियों के बावजूद चीन सरकार ह्यूमनॉइड रोबोट को भविष्य की रणनीतिक तकनीक मान रही है। इस वर्ष सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत वर्ष के अंत तक 100

से अधिक उच्च-मूल्य वाले व्यावहारिक क्षेत्रों में ह्यूमनॉइड रोबोट तैनात करने का लक्ष्य रखा गया है।बीजिंग का मानना है कि घटती कार्यशील आबादी और धीमी आर्थिक वृद्धि के बीच रोबोट भविष्य में उत्पादकता बढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन बन सकते हैं। साथ ही चीन इस क्षेत्र में अमेरिका, जापान और यूरोप पर तकनीकी बढ़त हासिल करना चाहता है। बाजार अनुसंधान संस्थानों के अनुसार दुनिया में ह्यूमनॉइड रोबोट निर्माण में चीन सबसे आगे निकल चुका है। देश में 140 से अधिक कंपनियां इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग और मजबूत विनिर्माण आपूर्ति श्रृंखला का लाभ मिलने से चीनी कंपनियां उत्पादन लागत तेजी से कम करने में सफल रही हैं। निवेश बैंक मॉर्गन स्टेनली का अनुमान है कि 2050 तक दुनिया में लगभग एक अरब ह्यूमनॉइड रोबोट उपयोग में हो सकते हैं।

स्पेन के जंगलों में भीषण आग: 12 की मौत, 23 लापता, हजारों हेक्टेयर राख

मैड्रिड, एजेंसी। स्पेन के अल्मेरिया प्रांत में भीषण जंगल की आग ने विदेशी नागरिकों की बस्ती को तबाह कर दिया. हादसे में 12 लोगों की मौत, 23 लोग लापता और 8 घायल हुए हैं. आग अब तक 3,200 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र जला चुकी है. यूरोप में लगातार पड़ रही भीषण गर्मी और सूखे ने वाइल्डफायर का खतरा बढ़ा दिया है.

स्पेन के दक्षिणी हिस्से में लगी भीषण जंगल की आग ने भारी तबाही मचाई है. आग की चपेट में आने से कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 23 लोग अब भी लापता हैं. मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है. यह हाल के वर्षों में स्पेन की सबसे घातक जंगल की आग में से एक मानी जा रही है. यह आग गुरुवार देर रात अल्मेरिया प्रांत में सिएरा डे लॉस फिलाब्रेस पहाड़ियों के पास एक दूरदराज इलाके में लगी, जहां बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक रहते हैं. उस समय पूरे स्पेन में भीषण गर्मी पड़ रही थी और सूखे की वजह से हालात पहले से ही खराब थे. ज्यादातर लोगों की मौत इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने अधिकारियों की घर के अंदर सुरक्षित रहने की सलाह नहीं मानी. कई लोग अपनी कारों से भागने लगे, जबकि कुछ पैदल निकल पड़े. कुछ लोग सूखी नदी के रास्ते भागे, लेकिन वह रास्ता उनके लिए मौत का जाल साबित हुआ. अधिकारियों के मुताबिक, चार मृतकों के ब्रिटिश नागरिक होने की आशंका है क्योंकि उनकी जली हुई कार में दाईं ओर स्टीयरिंग था, जैसा ब्रिटेन की गाड़ियों में होता है.

सात लोगों की मौत कार छोड़कर पैदल भागने के दौरान हुई. आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है. करीब 150 दमकलकर्मी और स्पेन की मिलिट्री इमरजेंसी यूनिट के 220 जवान आग बुझाने में जुटे थे. अब तक आग 3,200 हेक्टेयर (करीब 7,900 एकड़) जंगल और खेती की जमीन को जला चुकी है. इलाके की ऊबड़-खाबड़, सूखी जमीन, झाड़ियां, सूखी घास और तेज हवाएं आग बुझाने में सबसे बड़ी चुनौती बन रही हैं. लगातार पड़ रही हीटवेव ने पूरे इलाके को बारूद की तरह ज्वलनशील बना दिया है.

चीन पर 'बावी' का कहर... 20 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, भारी बारिश का 'रेड अलर्ट' जारी

बीजिंग, एजेंसी। प्रकृति के प्रकोप से जूझ रहे चीन में शनिवार रात एक और बड़ी आपदा ने दस्तक दी। शक्तिशाली तूफान 'बावी' शनिवार रात करीब 11:20 बजे पूर्वी चीन के झेजियांग प्रांत के तट से टकराया। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, यह इस साल का नौवां तूफान है, जिसने काउंटी स्तर के शहर युहुआन में लैंडफॉल किया।

जिस समय यह तूफान तट से टकराया, उस वक्त हवाओं की अधिकतम रफ्तार 40 मीटर प्रति सेकंड (करीब 144 किलोमीटर प्रति घंटा) दर्ज की गई, जिससे तटीय इलाकों में भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है।

20 लाख लोगों का ऐतिहासिक रेस्क्यू : ऑपरेशन तूफान की गंभीरता और इससे होने वाले संभावित जान-माल के नुकसान को देखते हुए चीनी प्रशासन ने व्यापक स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किए हैं। चीन के पूर्वी हिस्से से अब तक लगभग 20 लाख लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित आश्रय स्थलों पर पहुंचाया गया है। आपातकालीन स्थिति को देखते हुए राजधानी बीजिंग समेत देश के कई बड़े शहरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और राहत दलों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रखा गया है। प्रणाली चीन के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने अपनी चार स्तरीय चेतावनी प्रणाली में सबसे उच्च स्तर का 'रेड अलर्ट'

भारी बारिश के लिए जारी किया है। इसके साथ ही, तूफान के खतरे को देखते हुए 'ऑरेंज अलर्ट' भी लागू किया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले 24 घंटों में झेजियांग, उत्तरी फुजियान, उत्तर-पूर्वी जियांग्शी और दक्षिणी अनहुई सहित देश के एक बड़े हिस्से में अत्यधिक मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इतना ही नहीं, बीजिंग और हेबेई के कुछ हिस्सों में भी भारी जलजमाव और बाढ़ का खतरा बना हुआ है। चीन में तबाही मचाने से पहले इस तूफान ने पड़ोसी क्षेत्रों में भी काफी नुकसान पहुंचाया है। ताइवान के केंद्रीय मौसम प्रशासन के अनुसार, शनिवार को जब 'बावी' ताइवान के उत्तर से गुजरा, तब वहां 113 लोग घायल हो गए। सुरक्षा की दृष्टि से ताइवान के ज्यादातर इलाकों में स्कूल और दफ्तर बंद कर दिए गए और करीब 14,200 लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। वहीं, जापान के ओकिनावा प्रांत में ऊंची लहरों की चेतावनी जारी की गई है और पूरे इलाके में 200 से अधिक उड़ानों को रद्द करना पड़ा है। चीन के जल संसाधन मंत्रालय और स्थानीय प्रशासन ने लोगों से तटीय क्षेत्रों से दूर रहने और मौसम संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है। लगातार हो रही बारिश से नदियों के जलस्तर में वृद्धि और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा भी बढ़ गया है।

4000 जवान और रेंजर्स की 7 विंग; पीओके में बड़ी कार्रवाई की तैयारी में आसिम मुनीर?

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में 15 जुलाई को होने वाले बड़े विरोध प्रदर्शनों और लॉन्ग मार्च से पहले वहां की स्थानीय कठपुतली सरकार के हाथ-पांव फूल गए हैं। क्षेत्र में बड़े पैमाने पर होने वाले प्रदर्शन और अशांति को दबाने के लिए स्थानीय प्रशासन ने पाकिस्तान की सरकार से हजारों अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तत्काल तैनाती की मांग की है। सीएनएन-न्यूज 18 ने एक गोपनीय आधिकारिक दस्तावेज के हवाले से कहा है कि वहां के गृह विभाग ने इस्लामाबाद से 4,000 जवानों और पाकिस्तान रेंजर्स की सात विंग्स की तत्काल तैनाती की गुहार लगाई है। यह आपातकालीन कदम हाल के हफ्तों में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के प्रमुख नेता शौकत नवाज मीर और सैकड़ों अन्य कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद भड़के भयंकर जन आक्रोश की वजह से उठाया गया है। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय के सचिव को 8 जुलाई को भेजा गया यह पत्र बेहद संवेदनशील है, जिस पर अति आवश्यक और गोपनीय लिखा गया है। यह आदेश साफ तौर पर दर्शाता है कि पाकिस्तान समर्थित स्थानीय प्रशासन जेएएसी द्वारा चलाए जा रहे इस आंदोलन से बुरी तरह घबराया हुआ है। प्रशासन ने समिति पर लंबे मार्च, विरोध प्रदर्शन और धरने आयोजित करने का आरोप लगाया है। सरकार का दावा है कि इस आंदोलन के कारण पूरे क्षेत्र में एक अस्थिर सुरक्षा संकट पैदा हो गया है, जिससे निपटना अब स्थानीय सुरक्षा तंत्र के बस की बात नहीं रहा।

आधे जवानों के पास होंगे हथियार, आधे के पास दंगा-रोधी गियर : गोपनीय दस्तावेज के अनुसार मांगी गई यह अतिरिक्त फोर्स पीओके में पहले से ही तैनात भारी सुरक्षा बलों के अलावा होगी। दस्तावेज में साफ लिखा गया है कि इन सैनिकों की जरूरत प्रदर्शनों के खतरे को बेअसर करने, प्रशासन के इकबाल को बनाए रखने और थके हुए सुरक्षा अमले को मदद देने के लिए है। प्रशासन ने मांग की है कि आने वाले सुरक्षाकर्मियों में से 50 प्रतिशत पूरी तरह से आधुनिक हथियारों और गोला-बारूद से लैस होने चाहिए, जबकि शेष 50 प्रतिशत को दंगा-रोधी गियर दिया जाना चाहिए। आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि दंगा-रोधी उपकरणों की कोई कमी हो तो उसे बल की तैनाती से पहले पाकिस्तान के केंद्रीय स्टॉक से पूरा किया जाए। पीओके प्रशासन ने इस पूरी अशांति के लिए सीधे तौर पर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी को जिम्मेदार ठहराया है। सरकार का आरोप है कि पुंछ और रावलकोट में लगातार धरने दिए जा रहे हैं और पड़ोसी जिलों में रैलियां आयोजित कर लोगों को भड़काया जा रहा है। प्रशासन ने यह सनसनीखेज दावा भी किया है कि प्रतिबंधित समूहों से जुड़े सशस्त्र लोग मुजफ्फराबाद और मीरपुर डिवीजनों में शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं।

नेपाल में फिर जेन-जी प्रदर्शन; 3 दिन में 3 आत्मदाह:बेरोजगारी के खिलाफ गुस्सा

काठमांडू, एजेंसी। नेपाल में युवाओं की बढ़ती नाराजगी फिर से सड़कों पर दिखाई देने लगी है। पिछले तीन दिनों में तीन युवाओं ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया। इनमें से दो की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से झुलसा हुआ अस्पताल में भर्ती है।

प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह 'बालेन' के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। राजधानी काठमांडू में युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ने सरकार पर युवाओं में उम्मीद और भरोसा जगाने में विफल रहने का आरोप लगाया है। जेन-जी नेपाल संगठन ने प्रधानमंत्री बालेन शाह पर जनविरोधी और निरंकुश तरीके से शासन चलाने का आरोप लगाया है। संगठन का कहना है कि बजट व नीतियों में युवाओं के रोजगार और आय बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए।

2023 में बालेन शाह ने आत्मदाह को सरकार की विफलता कहा था 2023 की वह घटना भी चर्चा में है, जब प्रेम आचार्य ने आत्मदाह किया था। उस समय काठमांडू के मेयर रहे बालेन शाह ने इसे राज्य की चरम विफलता बताया था। अब मौजूदा घटनाओं पर उनकी चुप्पी विपक्ष और प्रदर्शनकारियों के निशाने पर है। नेपाल में लगातार सामने आ रही इन घटनाओं ने युवाओं की मानसिक स्थिति, बेरोजगारी और सरकारी नीतियों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों का मानना है कि यदि सरकार ने जल्द प्रभावी कदम नहीं उठाए तो विरोध और तेज हो सकता है। 2022 में मेयर बनने के बाद बालेन ने शहर की सफाई, विरासत संरक्षण और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती के कदम उठाए। अवैध निर्माण पर कार्रवाई से ट्रैफिक सुधरा, हालांकि इसका विरोध भी हुआ, खासकर सड़क किनारे दुकानदारों और झुग्गी बस्तियों के लोगों से। बालेन शाह का प्रभाव केवल प्रशासन तक सीमित नहीं रहा। पिछले साल सितंबर में हुए प्रदर्शनों के दौरान उनके गाने युवाओं के बीच गूंजते रहे। इन प्रदर्शनों में 77 लोगों की मौत हुई थी और इसके पीछे सोशल मीडिया पर प्रतिबंध, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और धीमी अर्थव्यवस्था को लेकर लोगों का गुस्सा था। 5 मार्च को हुए आम चुनाव में उनकी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की, जिससे नेपाल की पारंपरिक राजनीति को बड़ा झटका लगा। बालेन शाह ने झापा-5 सीट से पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को हराकर अपनी राजनीतिक ताकत साबित की। 35 साल की उम्र में प्रधानमंत्री पद संभालते ही वह नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं।

वेनेजुएला भूकंप मामले में 4,333 तक पहुंचा मौत का आंकड़ा, राहत कार्य के लिए लगभग 30 हजार लोग आए सामने

काराकास, एजेंसी। नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा कि वेनेजुएला में 24 जून को आए भूकंप के झटकों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,333 हो गई है। वहीं, राहत कार्य में मदद करने के लिए हजारों की संख्या में लोग सामने आ रहे हैं। रोड्रिगेज ने शनिवार को कहा कि 16,740 लोग घायल हुए हैं और 6,462 लोगों को बचाया गया है। अधिकारियों ने 18,000 से ज्यादा लोगों के लिए 94 अस्थायी कैंप बनाए हैं। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, उन्होंने कहा कि आपदा के मुश्किल समय में पीड़ितों की मदद के लिए लगभग 30,000 स्वयंसेवक सामने आए और सरकार ने उन्हें घर बनाने और रिपेयरिंग के कामों में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है।

रोड्रिगेज ने कहा कि क्योंकि कई परिवार बेघर हैं, इसलिए सरकार ने एक यूनिफाइड हाउसिंग रजिस्ट्री शुरू की है, जो जनगणना और भूकंप पीड़ितों को सरकार के आदेश पर मिलने वाली वित्तीय मदद के लिए एक डेटाबेस का काम करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार को उन लोगों को घर देने के लिए तेजी से कदम उठाने की जरूरत है जिन्होंने अपने घर हमेशा के लिए खो दिए हैं और जिन घरों को थोड़ा नुकसान हुआ है, उन्हें ठीक करने की जरूरत है। रोड्रिगेज ने कहा कि सरकार जब तक पक्के घर बन रहे हैं, तब तक सिंगल-फैमिली ट्राजिशनल हाउसिंग वाले कैंप लगाने का भी प्लान बना रही है। उन्होंने आगे कहा कि नेशनल असेंबली रेंटल लॉ में सुधार करने और भूकंप से प्रभावित परिवारों को घर खरीदने में मदद

करने के लिए क्रेडिट और सब्सिडी सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए आगे बढ़ेगी। अमेरिका और दूसरे देशों के आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से विदेश में जमा वेनेजुएला के फंड के बारे में, रोड्रिगेज ने कहा कि कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने अलग-अलग सरकारों को चिट्ठी भेजकर उन एसेट्स को रिलीज करने की अपील की है। इस बीच, वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने देश में हाल ही में आए भूकंप के पीड़ितों की मदद के लिए 28 देशों से मिली मानवीय मदद के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने यह टिप्पणी कराकास में एक राहत सामग्री संग्रह केंद्र का निरीक्षण करने के बाद की, जहां 24 जून को आए भूकंप के पीड़ितों के लिए बनाए गए अस्थायी राहत शिविरों में वितरण हेतु 2,000 टन से अधिक अंतरराष्ट्रीय सहायता सामग्री को छांटा और व्यवस्थित किया जा रहा है। रोड्रिग्ज ने कहा, 'वेनेजुएला उन देशों, दुनिया के लोगों और दुनिया की सरकारों को धन्यवाद देते नहीं थकता, जिन्होंने मदद की पेशकश की है। प्रत्येक देश यह देख सकेगा कि उसकी सहायता का उपयोग कैसे किया जा रहा है, ताकि वेनेजुएला के लोगों को उस देश की मैत्रीपूर्ण मदद का एहसास हो।'

रोड्रिग्ज ने कहा, 'इस त्रासदी पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद, वेनेजुएला जानता है कि यह अकेला नहीं है। सबसे जरूरी बात भविष्य की ओर देखना है, हम कैसे ठीक होंगे, हम प्रभावित इलाकों को कैसे फिर से बनाएंगे।

स्वामी, मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़्सेट एफपी, 149 प्लोट 26 खोडीयारनगर, सिद्धिविनायक मंदीर के पास ,भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सूरत के नासिरनगर का ध्वस्तीकरण नगर आयुक्त के निर्देश पर हुआ'

आयुक्त ने मुझे मिला संदेश फॉरवर्ड किया था, निलंबित कार्यपालक अभियंता का हाईकोर्ट में बड़ा खुलासा

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत के नासिरनगर में कथित अवैध ध्वस्तीकरण (डिमोलिशन) मामले में निलंबित कार्यपालक अभियंता (एग्जीक्यूटिव इंजीनियर) सुजल प्रजापति ने सूरत महानगरपालिका (SMC) और नगर आयुक्त नागराजन को पक्षकार बनाते हुए गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने अपने निलंबन को चुनौती देते हुए कहा है कि बिना किसी विभागीय जांच के उन्हें निलंबित किया गया। उनका दावा है कि उन्हें निलंबित करने का अधिकार स्टैंडिंग कमेटी का है, लेकिन नगर आयुक्त ने सीधे निलंबन का आदेश जारी किया।

याचिका में यह भी कहा गया है कि नासिरनगर का ध्वस्तीकरण नगर आयुक्त के निर्देश पर ही कराया गया था।

सुजल प्रजापति ने अपनी याचिका में कहा है कि नगर आयुक्त का कहना है कि यह ध्वस्तीकरण अनधिकृत था। SMC ने इस मामले की जांच के लिए एक समिति बनाई और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ के दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि उन्होंने यह कार्रवाई अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर की थी। उस समय वे रोड विभाग में कार्यरत थे और उनके ऊपर केवल एक ही वरिष्ठ अधिकारी थे।

उन्होंने दावा किया कि 21 मई 2026 को नगर आयुक्त के आधिकारिक मोबाइल नंबर से उन्हें एक फॉरवर्ड किया हुआ संदेश प्राप्त हुआ था। उन्होंने कहा कि इस संदेश की सत्यता के संबंध में वे अदालत में शपथपत्र (एफिडेविट) दाखिल करने के लिए भी तैयार हैं। उनके अनुसार, उन्हें वार्ड नंबर-7 में चंद्रशेखर आजाद ब्रिज के पास प्रस्तावित 60 फीट टीपी रोड के लिए अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था।

याचिका में कहा गया है कि किसी व्यक्ति ने नगर आयुक्त को संदेश भेजा था, जिसे आयुक्त ने आगे उन्हें फॉरवर्ड कर दिया। इसी निर्देश के आधार पर उन्होंने कार्रवाई की। दूसरी ओर, जिस हाईकोर्ट की दूसरी पीठ में अवैध ध्वस्तीकरण का मामला चल रहा है, वहां नगर आयुक्त ने शपथपत्र में कहा है कि यह जांच की जा रही है कि ध्वस्तीकरण किसके निर्देश पर

हुआ, जबकि वास्तविकता यह है कि कार्रवाई उनके ही निर्देश पर हुई थी।

सुजल प्रजापति ने कहा कि 3 जून को उन्हें नासिरनगर के प्रभावित लोगों के पुनर्वास (रिलोकेशन) के लिए सर्वे करने का भी निर्देश दिया गया था। इस कार्रवाई से 59 अनधिकृत मकान धारक प्रभावित हुए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच में यह स्पष्ट नहीं किया जा रहा कि ध्वस्तीकरण का आदेश किसने दिया था। उप नगर आयुक्त की अध्यक्षता वाली जांच समिति के समक्ष भी यह तथ्य सामने आया कि कार्रवाई नगर आयुक्त के निर्देश पर हुई थी, फिर भी अदालत में यह कहा गया कि उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया। उन्होंने हाईकोर्ट से निलंबन रद्द कर संरक्षण देने की मांग की है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि अवैध ध्वस्तीकरण का मामला हाईकोर्ट पहुंचने के बाद नगर आयुक्त ने स्वयं को बचाने के लिए यह पूरी कार्रवाई की। सुजल प्रजापति ने अदालत में नगर आयुक्त के साथ हुई चैट के स्क्रीनशॉट भी पेश किए हैं। उन्होंने बताया कि SMC के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल 'माय सूरत 'पर ध्वस्तीकरण से जुड़ी रील साझा की गई थी और उसे एक आधिकारिक ग्रुप में भी भेजा गया था। निलंबन के बाद उन्हें उस ग्रुप से हटा दिया गया। उनका कहना है कि पहले उनके काम की प्रशंसा की गई और बाद में उन्हें ही निलंबित कर दिया गया।

ध्वस्तीकरण के समय नगर आयुक्त ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि यह कार्रवाई SMC के आदेश पर नहीं हुई। बाद में उन्होंने कहा कि केवल सड़क चौड़ीकरण के लिए सीमांकन (डिमार्केशन) किया जाना था, ध्वस्तीकरण नहीं। हालांकि, याचिका में दावा किया गया है कि ध्वस्तीकरण से पहले ही SMC के संबंधित विभाग ने टोरेंट पावर को बिजली आपूर्ति काटने के निर्देश दिए थे। मुख्य ध्वस्तीकरण को चुनौती देने वाली याचिका पर प्राधिकरण ने अदालत से समय मांगा है और अब इस मामले की सुनवाई 20 जुलाई को होगी।

घटनास्थल पर मौजूद SMC के जयंग रामजीवाला सहित कुल पांच इंजीनियरों को निलंबित किया गया था। इन सभी ने भी हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं। सूरत में 29 और 30 मई 2026 को वेड दरवाजा के पास स्थित वर्षों पुराने नासिरनगर इलाके में भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच लगभग 100 मकानों को ध्वस्त किया गया था। इस कार्रवाई को गुजरात के इतिहास के सबसे रहस्यमय ध्वस्तीकरणों में से एक माना जा रहा है। पूरे मामले में कई सवाल अब भी अनुत्तरित हैं और इस कथित 'भूतिया डिमोलिशन 'का असली जिम्मेदार कौन है, इसका खुलासा अभी होना बाकी है। 1 जुलाई 2026 को सूरत महानगरपालिका ने सुजल प्रजापति, जयंग रामजीवाला, मोनिक गढ़िया, अर्पण परमार और नरेश गलचर सहित पांच इंजीनियरों को निलंबित कर दिया था। इन सभी के खिलाफ मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है।

हाईकोर्ट ने नगर आयुक्त से मांगा शपथपत्र

गुरुवार को सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि सूरत में बाढ़ की स्थिति के कारण SMC प्रशासन राहत कार्यों में व्यस्त है, इसलिए समय दिया जाए। इस पर हाईकोर्ट ने नगर आयुक्त को इस मामले में शपथपत्र दाखिल करने का आदेश दिया। सरकारी वकील ने यह भी कहा कि अदालत के समक्ष केवल चुनिंदा स्क्रीनशॉट प्रस्तुत किए गए हैं। हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया टिप्पणी की कि ऐसा प्रतीत होता है कि नगर आयुक्त ने वास्तव में याचिकाकर्ता को संदेश फॉरवर्ड किया था। अदालत ने कहा कि नगर आयुक्त अपना पक्ष शपथपत्र के माध्यम से रखें। मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी।

सुजल प्रजापति की कथित भूमिका

1. श्रीराम एजेंसी को तीन पोकलेन मशीनें, दो जेसीबी ब्रेकर और 60 मजदूर लाने के निर्देश दिए।
2. संबंधित क्षेत्र उनका ज़ोन न होने के बावजूद वे मौके पर पहुंचे।
3. संबंधित ज़ोन के जिम्मेदार अधिकारी को वरिष्ठ अधिकारी का संदेश दिखाकर किनारे कर दिया।
4. पुलिस की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण शुरू करने का निर्देश सुजल प्रजापति ने दिया।
5. जिस विभाग की जिम्मेदारी उनके पास थी, उसके कोई अधिकारी उनके साथ मौजूद नहीं थे।

पांच इंजीनियर निलंबित, सभी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

फिर आया धमकी भरा ईमेल...

सूरत न्यू कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत की न्यू कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पूरे परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कोर्ट के आधिकारिक सरकारी ईमेल पर एक धमकी भरा संदेश प्राप्त हुआ, जिसमें दावा किया गया कि कोर्ट परिसर में बम रखा गया है। ईमेल मिलते ही प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गईं।

धमकी मिलते ही बम निरोधक दस्ता (बॉम्ब स्क्वॉड), सूरत पुलिस की विभिन्न टीमें और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गईं। सुरक्षा बलों ने कोर्ट परिसर में व्यापक तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। परिसर के हर संदिग्ध स्थान की बारीकी से जांच की जा रही है ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते टाला जा सके।

गुजरात के सूरत में हुई इस घटना को सुरक्षा एजेंसियां बेहद गंभीरता से ले रही हैं। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि यह ईमेल कहां से भेजा गया, किसने भेजा और इसके पीछे क्या उद्देश्य था। फिलहाल कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह सख्त कर दी गई है और किसी भी अप्रिय घटना से बचाव के लिए सभी आवश्यक एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं।

इस धमकी के बाद न्यायिक तंत्र, वकीलों और आम नागरिकों में चिंता का माहौल है। हालांकि, जांच पूरी होने तक अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है।

सूरत में बाढ़ का पानी उतरने के बाद त्वचा रोग का खतरा बढ़ा 4 हजार मरीजों में से 825 का स्किन डिजीज का इलाज

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत में खाड़ी और बाढ़ का पानी उतरने के बाद अब स्वास्थ्य पर इसका असर दिखाई देने लगा है। सूरत महानगरपालिका (SMC) द्वारा लगाए गए 18 स्वास्थ्य शिविरों में पिछले तीन दिनों के दौरान लगभग 4,000 लोगों की जांच की गई, जिनमें से 825 लोगों का त्वचा रोग (स्किन डिजीज) का उपचार किया गया। इसके अलावा बुखार, दस्त और उल्टी के मामले भी सामने आए हैं। महामारी फैलने से रोकने के लिए नगर निगम ने मेडिकल कैंप अगले शनिवार तक जारी रखने का फैसला किया है। गंभीर स्थिति वाले 14 मरीजों को अस्पताल रेफर किया गया है।

भारी बारिश और खाड़ी में आई बाढ़ के बाद अब सूरत में स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ने लगी हैं। बाढ़ का पानी उतरने के बाद गंदगी, कीचड़ और दूषित पानी के लंबे समय तक संपर्क में रहने से त्वचा रोग के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। नगर निगम द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगाए गए स्वास्थ्य शिविरों में सबसे अधिक मरीज त्वचा संबंधी बीमारियों से पीड़ित पाए गए।

स्थिति सामान्य होने के बाद नगर निगम ने महामारी की रोकथाम को प्राथमिकता देते हुए 11 जुलाई से बाढ़ प्रभावित इलाकों में मेडिकल कैंप शुरू किए हैं, ताकि लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत न पड़े और उन्हें मौके पर ही तत्काल इलाज मिल सके।

नगर निगम ने अठवा ज़ोन में 1, उधना ज़ोन-ए में 5, वराछा ज़ोन-ए में 3, सरथाणा ज़ोन में 2 और लिंबायत ज़ोन में 4 सहित कुल 18 स्थानों पर स्वास्थ्य शिविर संचालित किए हैं। इन शिविरों में मेडिकल ऑफिसर, त्वचा रोग विशेषज्ञ, लैब तकनीशियन और अन्य स्वास्थ्यकर्मी नागरिकों की जांच कर आवश्यक दवाएं उपलब्ध करा रहे हैं।

11 जुलाई से रविवार दोपहर तक लगभग 4,000 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई। इनमें सबसे अधिक 825 मरीज त्वचा रोग से पीड़ित पाए गए, जो बाढ़ के बाद सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बनकर सामने आया है। इसके अलावा 357 लोगों में बुखार, 264 लोगों में सामान्य दस्त और 82 लोगों में दस्त-उल्टी की शिकायत दर्ज की गई। वहीं अन्य विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित करीब 2,000 मरीजों का भी उपचार किया गया।

जांच के दौरान गंभीर हालत वाले 14 मरीजों को आगे के इलाज के लिए अस्पताल रेफर किया गया। दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग की टीम प्रभावित क्षेत्रों में घर-घर जाकर ओआरएस (ORS) के पैकेट वितरित कर रही है, लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रही है तथा महामारी की रोकथाम के लिए लगातार सर्विलांस (निगरानी) भी कर रही है।

नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार वर्तमान स्थिति को देखते हुए त्वचा संक्रमण, बुखार और जलजनित बीमारियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगाए गए सभी मेडिकल कैंप अगले शनिवार तक संचालित रहेंगे।

सूरत के गोडादरा रोड स्थित टेक्सटाइल मार्केट में 7 दिनों से दुकानें बंद, लाखों-करोड़ों के नुकसान के बावजूद प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचे

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत के गोडादरा रोड स्थित टेक्सटाइल मार्केट में बाढ़ का पानी भर जाने से व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। दुकानों और गोदामों में पानी घुसने से लाखों-करोड़ों रुपये का कपड़ा और अन्य सामान खराब हो गया है, जिससे व्यापारियों की कमर टूट गई है। बाढ़ के बाद से टेक्सटाइल मार्केट की दुकानें पिछले 7 दिनों से बंद हैं। सातवें दिन भी व्यापारी अपनी दुकानें नहीं खोल सके हैं। सूरत में आई विनाशकारी बाढ़ ने व्यापारियों को भारी आर्थिक संकट में डाल दिया है। दुकानों और गोदामों में भरे पानी ने वर्षों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। कई बेसमेंट में अब भी पानी भरा हुआ है, जबकि करोड़ों रुपये का माल पूरी तरह भीगकर खराब हो चुका है।

व्यापारियों का कहना है कि पोददार आर्केड स्थित टेक्सटाइल मार्केट में स्वयं उपमुख्यमंत्री पहुंचे थे, जहां उन्होंने नुकसान का जायजा लिया, व्यापारियों को सांत्वना दी और बीमा संबंधी जानकारी भी ली। लेकिन गोडादरा रोड की इस टेक्सटाइल मार्केट में

अब तक प्रशासन का कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा है और न ही नुकसान का कोई सर्वे किया गया है। भारी नुकसान के कारण व्यापारी बेहद परेशान हैं।

व्यापारियों के अनुसार, दुकानों में कमर तक पानी भर गया था, जिससे करोड़ों रुपये का माल बर्बाद हो गया। एक सप्ताह बीत जाने के बावजूद कई स्थानों पर अब भी पानी जमा है। इस बाढ़ से छोटे और बड़े सभी कपड़ा व्यापारियों को नुकसान हुआ है। करीब 250 दुकानों में पानी घुस गया था। छोटे व्यापारी, जो मुश्किल से अपनी दुकान का किराया चुका पाते हैं, उन्हें भी 20-20 लाख रुपये तक का नुकसान हुआ है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह डगमगा गई है।

दुकानों में खराब हुआ माल अभी भी वहीं पड़ा हुआ है। व्यापारी दुकानों की सफाई और खराब माल बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन आरोप है कि टेम्पो और अन्य वाहन अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही, जिससे खराब सामान हटाने का काम भी नहीं हो पा रहा है। इसके कारण व्यापार पूरी तरह ठप हो गया है और व्यापारियों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है।

स्थानीय लोगों और व्यापारियों का कहना है कि बाढ़ का पानी उतरने के बाद भी कई इलाकों में बिजली और अन्य आवश्यक सुविधाएं पूरी तरह बहाल नहीं हुई हैं। इसी वजह से पूरे टेक्सटाइल मार्केट में व्यापारिक गतिविधियां शुरू नहीं हो सकी हैं। व्यापारियों ने यह भी आरोप लगाया कि प्रशासन की ओर से अब तक किसी प्रकार की राहत या पुनर्वास संबंधी प्रभावी कार्रवाई शुरू नहीं की गई है, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

भगवान के महाप्रसाद की तैयारी में महिला श्रद्धालुओं की अनोखी सेवा सूरत की महिलाओं ने संभाली प्रसाद बनाने की जिम्मेदारी

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत में भगवान जगन्नाथ की 45वीं रथयात्रा से पहले लंका विजय ओवारा में महिला श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद तैयार करने का सेवा यज्ञ शुरू कर दिया है। मंदिर परिसर में 1,000 किलो से अधिक मूंग, 1,000 किलो से अधिक शीरा (सूजी का हलवा) तथा अन्य प्रसाद बनाने की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। हजारों श्रद्धालुओं को भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद स्वरूप महाप्रसाद मिल सके, इसके लिए आयोजक और श्रद्धालु पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ तैयारियों में जुटे हैं।

भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा में महाप्रसाद का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। भगवान को अर्पित किए जाने वाले मूंग और शीरे का प्रसाद बाद

में श्रद्धालुओं में वितरित किया जाता है। भगवान को भोग लगाने के बाद मिलने वाला यह महाप्रसाद केवल भोजन नहीं, बल्कि भगवान के आशीर्वाद और कृपा का प्रतीक माना जाता है। इसी भावना को साकार करने के लिए सूरत के लंका विजय ओवारा से निकलने वाली 45वीं रथयात्रा से पहले महिला श्रद्धालुओं ने प्रसाद तैयार करने की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली है।

पुरी और अहमदाबाद की तरह सूरत में भी वर्षों से आषाढ़ी बीज के दिन भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा निकाली जाती है। इस वर्ष भी आगामी गुरुवार को निकलने वाली रथयात्रा में हजारों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। सभी भक्तों को भगवान का प्रसाद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजकों ने पहले से ही व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। तापी नदी के किनारे अमरोली ब्रिज के नीचे स्थित लंका विजय हनुमानजी मंदिर में महिला श्रद्धालु पूरी निष्ठा के साथ महाप्रसाद बनाने की सेवा में जुटी हुई हैं।

रथयात्रा की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में महिलाएं मूंग की सफाई, प्रसाद के लिए आवश्यक सामग्री तैयार करने और अन्य सेवा कार्यों में लगी हुई हैं। भजन-कीर्तन के मधुर वातावरण के बीच चल रही यह सेवा पूरे मंदिर परिसर को भक्तिमय बना रही है।

मंदिर के महंत सीताराम बापू ने बताया कि 45वीं रथयात्रा में हजारों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आएंगे। प्रत्येक श्रद्धालु तक पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण प्रसाद पहुंचे, इसके लिए पहले से ही व्यापक योजना बनाई गई है। इस वर्ष 1,000 किलो से अधिक मूंग, 1,000 किलो से अधिक शीरा तथा श्रीफल (नारियल) सहित अन्य प्रसाद भी तैयार किए जाएंगे। प्रसाद निर्माण में शामिल सभी श्रद्धालु इसे भगवान जगन्नाथ की सेवा मानकर पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ कार्य कर रहे हैं।

महिला श्रद्धालुओं का कहना है कि भगवान के महाप्रसाद की तैयारी में सेवा करने का अवसर उनके जीवन का सौभाग्य है। कोई मूंग की सफाई कर रही है, कोई प्रसाद की सामग्री व्यवस्थित कर रही है, तो कोई रसोई की प्रारंभिक तैयारियों में सहयोग दे रही है। रथयात्रा से पहले मंदिर परिसर में सुबह से शाम तक सेवा और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है।

वहीं,जहांगीरपुरा स्थित मंदिर ने इस वर्ष बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए जल्दी खराब होने वाली बूंदी के स्थान पर साकरिया दाना (सूखा प्रसाद) वितरित करने का निर्णय लिया है। श्रद्धालुओं के घरों पर ही इस सूखे प्रसाद के पैकेट तैयार किए जा रहे हैं, ताकि बड़ी संख्या में आने वाले भक्तों तक प्रसाद आसानी और व्यवस्थित रूप से पहुंचाया जा सके।